## सम्पादकीय

# सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने जज साहब को ही कर दिया गुमराह, मीलॉर्ड ने जताई चिंता

हर अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वह अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाएगा। वकालत के पेशे में नैतिक दायित्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है। इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियां और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास करता है। अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती हैं। दरअसल, वकील अपने मुवक्किल और न्यायाधीश के बीच एक सेतु होता है। इस तरह कई बार न्यायाधीशों को भी वकीलों की जिरह से कानून की बहुत सारी बारीकियों समझने में मदद मिलती है। मगर वकील जब इस विश्वास के रिश्ते का फायदा उठा कर, जानबूझ कर अदालत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, तो उससे पूरी न्याय प्रक्रिया गुमराह होती और न्याय का रास्ता बाधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि वकीलों के झूठे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि पिछले तीन-चार हफ्तों में सात-आठ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें वकीलों ने झूठे बयान देकर अपने मुवक्किल की सजा माफ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई।

कानून में यह प्रावधान है कि किसी दोषी के अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य आदि के मद्देनजर उसकी सजा कम या खत्म की जा सकती है। मगर उसके लिए न्यूनतम अवधि की सजा काटना जरूरी होता है। इसी तरह कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से कैदियों को कुछ दिन फरलो पर बाहर रहने की इजाजत दी जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कुछ वकील अपने मुवक्किल को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मामलों का संज्ञान लिया, उनमें देखा गया कि वकीलों ने झूठे बयान और दलील देकर सजा माफी की गुहार लगाई। एक मामले में सजायाफ्ता चार कैदियों को लेकर कहा गया कि वे चौदह वर्ष की सजा काट चुके हैं। यह भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सजा दी गई थी। मगर अदालत को पता चला कि उन्होंने न केवल चौदह वर्ष की सजा पूरी नहीं की थी, बल्कि चारों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। इसी तरह एक मामले में बताया गया कि फरलो पर बाहर गए सभी कैदियों की फरलो अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही अन्य मामले देखे गए। निस्संदेह इस प्रवृत्ति से न्यायिक शुचिता प्रश्नांकित होती है। हालांकि इस संदर्भ में यह भी चिंताजनक है कि जघन्य अपराध के दोषियों को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पैदा कहां से हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं, जिनमें राज्य सरकारों ने हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजायाफ्ता लोगों की सजा माफी की सिफारिश की। कुछ अपराधियों को बार-बार फरलो दी गई। समझना मुश्किल नहीं है कि इस राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विस्तार हुआ है। फिर, वकालत के पेशे में भी नैतिकता का प्रकट ह्रास हुआ है।

# 'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

**भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है।**

ललित गर्ग।

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'एक देश एक चुनाव' के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के 'एक देश एक चुनाव' वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है। लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्संदेह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है।

निश्चित ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावों में कुल सरकारी खर्च 6600 करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश को देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ तो डालते ही है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होने के बाद सबसे पहले अपने भारी





खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेगा। अतः असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करने पर सभी राजनैतिक दलों में एक सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष को अपने राजनीतिक हितों की बजाय देशहित को सामने रखकर इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिये एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता के यक्ष प्रश्न को भी सामने रखकर इस पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादी का मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साह का महाकुंभ देखता है, जहाँ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालाँकि, इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच, विभिन्न स्तरों-स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय-पर चुनावों के समन्वय को लेकर बहस ने हाल के वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक दशक के शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में 'एक देश, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में उसने 'एक देश, एक चुनाव' को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करते हुए सभी राजनैतिक दलों के सामने निजी हित एवं चुनाव जीतने का गणित सामने आ जाता है। भारत की असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चे से चुनाव कराने की बात होती है तो इस राह को अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्र में यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। जब दुनिया के अनेक देशों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारत में इसे लागू करने में इतने किन्तु-परन्तु क्यों है? देश में इसे लागू करने से सरकार कुछ-कुछ समय बाद चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन यानी विकास योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा। इन सब स्थितियों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जाने पर क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाले नुकसान एवं अन्य स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा।

## आज का राशिफल

**मेष**
आपका आज का दिन सामाजिक प्रवृत्तियों और मित्रों के साथ दौड़-धूप में व्यतीत होगा। आज के दिन बुजुर्गों और पूजनीय व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आज कोई भी सोच-विचार करने के बाद ही बोलें।

**वृष**
नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। सगे-संबंधियों तथा मित्रों का आपके यहां आगमन होने से आनंद अनुभव होगा। कहीं यात्रा होने की संभावना है। भाग्य वृद्धि का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे, तो शांति मिलेगी।

**मिथुन**
भागीदारों के साथ मतभेद होगा। कुछ खास दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी। कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होने की आशंका है। आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी। बीमारी में राहत महसूस होगी।

**कर्क**
पैसे की तंगी महसूस होगी। दुर्घटना, ऑपरेशन का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। ईश्वर भक्ति से राहत महसूस कर सकेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है। फिर भी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

**सिंह**
बाहर का खाने-पीने के कारण स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नए संबंध तकलीफदायक साबित होंगे।

**कन्या**
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज आप कल्पना और सृजनशक्ति का उपयोग कर सकेंगे। संतान की प्रगति होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। संयमित वाणी आपको बहुत-सी मुसीबतों से बचा लेगी।

**तुला**
प्रिय व्यक्ति के साथ की गई मुलाकात रोमांचक रहने की उम्मीद है। तन-मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा। अत्यधिक विचारों से मन विचलित रहेगा। आज किसी के साथ बौद्धिक चर्चा या वाद-विवाद हो सकता है।

**वृश्चिक**
जमीन, वाहन वगैरह की खरीदारी के दस्तावेज बनवाने में सावधानी रखें। गूढ़ रहस्यमय विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर विशेष रहेगा। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। भाई-बहनों के साथ मेल-जोल बना रहेगा।

**धनु**
सरकार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिकूल संयोग के बनने से आपके कार्य में विलंब होगा। शरीर में ताजगी और मन में उत्साह का अभाव रहेगा। पेट के रोग सताएंगे। नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दुख होगा।

**मकर**
आज आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। नौकरीपेशा वालों के लिए आज का दिन शुभ है। उन्हें आय वृद्धि या पदोन्नति का समाचार मिलेगा। सरकारी लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन आपका उत्साह बढ़ाएगा।

**कुंभ**
आज के दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से भय अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों तथा सगे- संबंधियों के साथ अनबन होने की आशंका है। कोशिश करें कि किसी के साथ विवाद न हो। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**मीन**
सरकारी काम में बाधा होगी। महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखना उचित रहेगा। संतान के साथ मतभेद होगा। विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। आज मन का नकारात्मक व्यवहार आपको हताश करेगा। धन खर्च होने की संभावना है।

## शख्सियत

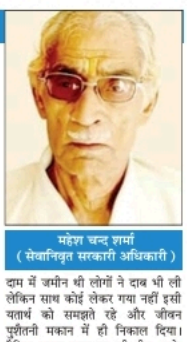

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं मेरे लिए सुपर स्टार मेरे पापा। जी हां एक पुत्र के लिए उसका पिता ही असली हीरो होता है ऐसे ही श्री महेश चन्द शर्मा जोकि जिला उद्योग केन्द्र से स्वेच्छिक सेवानिवृत हुए हैं। जोकि अब अपने जीवन के नोवें दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुरू से ही एक अलग अंदाज में जीवन जीने वाले श्री महेश चन्द शर्मा बेहद ईमानदार व कर्तव्य निष्ट कर्मी के रूप में रहे हैं। हमेशा जिस भी विभाग में नौकरी की जहां पूरी दमदारी के साथ नौकरी की। पहले न्यास विभाग में रहे,उसके बाद बाटमाप विभाग में रहे उसके बाद जिला उद्योग केन्द्र में रहे जहां से स्वेच्छिक सेवानिवृत ले ली। श्री महेश शर्मा बताते हैं कि भिवाड़ी में सन 1961 में जब बसावट नहीं थी तो सरकारी की कल्याण कारी योजनाओं और उद्योगपतियों को भूमि व ऋण उपलब्ध कराने के लिए टैंट लगाकर वहां शिविर लगाते थे। जेयष्ठ की तपती धूप में जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, हलक सुख जाते थे तो वहां कैम्प कर लोगों को उद्योगों से जोड़ा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ईमानदारी इतनी कि जब हम छोटे थे तो घर पर कोई उद्योगपति आते तो उनसे अच्छे से मिल लेते लेकिन मिठाई का डिब्बा नहीं लेते थे,तब हम छोटे थे ईमानदारी बेईमानी क्या होती है समझ नहीं आता था बस यही लगता था कि हमारे पापा सबसे बुरे हैं कोई मिठाई देने आता है और ये लेते ही नहीं हैं। धीरे-धीरे बड़े हुए तो जमीर की जीवन में क्या अहमीयत है इसका ज्ञान हुआ और हमारे पिता ही हमारे असली हीरो बन गए। सबके दुःख दर्द में हमेशा मदद करना हमारे पिताजी की संस्कारी विरासत है। संतोष धन भी उनकी परवरिश का एक बड़ा हिस्सा है। वो कहते हैं कि उनके समय में अलवर शहर के परकोटे के बाहर कोड़ियों के दाम में जमीन थी लोगों ने दाब भी ली लेकिन साथ कोई लेकर गया नहीं इसी यतार्थ को समझते रहे और जीवन पुशैतनी मकान में ही निकाल दिया। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके स्वास्थ्य जीवन की कामना करती है।



महेश चन्द शर्मा
( सेवानिवृत सरकारी अधिकारी )

जय हिन्द
रूपक शर्मा

## आज का इतिहास

### 18 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फिलिप अगुस्टस 1180 में फ्रांस का राजा बना।
- क्रिस्टोफर कोलंबस 1502 में कोस्टारिका पहुँचे।
- इंग्लैंड के राजा जेम्स 1615 में प्रथम के एंबेसडर थामस रॉ जहाँगीर से मिलने सूरत पहुँचा।
- फर्डिनैंड द्वितीय ने 1635 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- तुर्की तथा ऑस्ट्रिया ने 1739 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- अंग्रेजों ने 1803 में ओडिशा के पुरी पर कब्ज़ा किया।
- इसी दिन शेक्सपीयर के मैकबेथ नाटक के साथ रॉयल थिएटर को 1808 में मरम्मत के बाद सजा धजा कर दोबारा खोला गया।
- लंदन में 1809 को रॉयल ऑपेरा हाउस खुला।
- चिली ने 1810 में स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- न्यूयार्क टाइम्स अखबार ने 1851 में प्रकाशन शुरू किया।
- नीदरलैंड के रोटरडम शहर में 1905 को विद्युत ट्रामलाइन की शुरुआत हुई।
- हॉलैंड में 1919 को महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
- हंगरी लीग ऑफ नेशंस में 1922 को शामिल हुआ।
- न्यूयार्क में 1923 को समाचारपत्र प्रकाशकों की हड़ताल हुई जो 23 सितंबर तक चली।
- अमेरिका के मियामी में 1926 को चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत।
- जापान की सेना ने 1931 को पूर्वोत्तरी चीन में स्थित मन्चूरी के क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। यह कब्ज़ा चीन और जापान के बीच दूसरे युद्ध का कारण बना। जापानियों ने मन्चूरी पर नियंत्रण के पश्चात वहाँ मेन्टको की पिटठू सरकार स्थापित कर दी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1947 को पारित हुआ।
- अमेरिका में वायु सेना का गठन 1947 में हुआ।
- तत्कालीन सोवियत संघ ने 1961 में नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।
- नागालैंड ने 1967 में अंग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया।
- अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौजूदगी में 1978 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादत और इसरायल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन शांति के लिए राजी हुए थे।
- पहली महिला पायलट ने 1986 में बम्बई से गोआ के बीच उड़ान भरी।
- अमेरिका और सोवियत संघ ने 1987 में मध्यम दूरी के मिसाइल को हटाने के लिये हस्ताक्षर किये।
- बर्मा ने 1988 में अपना संविधान रद्द किया।
- मुम्बई से पहली बार महिला चालकों ने 1986 को जेट विमान उड़ाया।
- सं.रा. अमेरिका ने 1997 में 'होलोग' नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, ओज़ोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने सन् 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बन्द करने का निश्चय किया।
- सं.रा. अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का 1 अरब डॉलर बकाये की घोषणा 1998 में की।
- ढाका-अगरतला बस सेवा 2003 में शुरू।
- रूसी राकेट सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2006 में रवाना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की दौड़ में अफगानिस्तान के पूर्व वित्तमंत्री अशरफ़ गनी शामिल।
- कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जी.वी. मिश्रा को 2007 में विशेष सम्मान से नवाजा गया।

## विशेष आलेख

# बांग्लादेश तख्तापलट में लगी थी अमेरिका की कई एजेंसियाँ

रामस्वरूप रावतसरे

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने की योजना 2019 में ही बन गई थी। अमेरिका की अलग-अलग एजेंसियाँ इस काम में लगाई गईं थी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए लाखों डॉलर भी पानी की तरह बहाए गए। हसीना की सत्ता पलटने के लिए अमेरिका ने अलग-अलग एजेंसियों का प्रयोग किया। यह सारे खुलासे अखबार द सन्डे गार्जियन को मिले अमेरिकी कागजों से हुआ है। सन्डे गार्जियन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस पूरी योजना का हिस्सा वह अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू भी था, जो सत्ता परिवर्तन का मास्टर माना जाता है।



बांग्लादेश में सत्ता बदलने के लिए अमेरिकी एजेंसियों का जमकर इस्तेमाल हुआ। यह एजेंसियाँ सरकार से पैसा लेती है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का प्रमुख काम करने वाली एक ऐसी ही एजंसी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टिट्यूट है। आईआरआई अमेरिका की यूएसएआईडी और एनईडी नाम की एजेंसियों के लिए काम कर रही थी और उनका उद्देश्य पूरा कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दोनों एजेंसियों से पैसा लेकर ही आईआरआई ने बांग्लादेश में अपना काम चालू किया। आईआरआइ ने इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया और यह जनवरी 2021 तक चला। आईआरआइ ने कहा इस कायर्क्रम का उद्देश्य बांग्लादेश के भीतर उन लोगों को आवाज देना है, जो हसीना की दमनकारी सत्ता के विरुद्ध खड़े हो सकें। आईआरआइ ने अपने इस कार्यक्रम में एलजीबीटी, बिहारी और बाकी समुदायों के लोगों के समूहों को समर्थन दिया। इसके तहत 77 'एक्टिविस्ट' को ट्रेनिंग भी दी गई। इन लोगों को बड़ी धनराशि भी दी गई। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि अमेरिका उन लोगों को अपने पक्ष में बोलने के लिए तैयार कर रहा था जो हसीना का विरोध कर सकें।

आईआरआइ ने 2021 में एक और प्रोग्राम चलाया था। इसके लिए उसे अमेरिकी एजेंसी एनएमडी से 9 लाख डॉलर की मदद मिली थी। इस कार्यक्रम के तहत आईआरआइ ने उन नेताओं को तैयार करने का लक्ष्य रखा था जो आगे जाकर बड़ी आवाज बन सकें। इसके तहत आईआरआइ ने बांग्लादेश की कई पार्टियों के लोगों को सहायता करती जिससे वह बड़े पदों पर पहुँच सके। आईआरआइ ने अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए कई ऐसे लोगों को उन कार्यक्रमों में शामिल करवाया जहाँ अमेरिकी राजनयिक और अधिकारी आते थे।

आईआरआइ ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गिराने के लिए अलग-अलग संस्थानों का विकल्प सोचा था। एक रिपोर्ट में आईआरआइ ने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सेना और यहाँ के कारोबारी शेख हसीना की सत्ता पलट सकते हैं। हालाँकि, आईआरआइ ने पाया कि अधिकांश बड़े कारोबारी शेख हसीना की आवामी लीग का समर्थन करते हैं और सेना के बड़े अधिकारी भी सरकार के प्रति कोई खास गुस्सा नहीं है। अपनी रिपोर्ट में आईआरआइ ने कहा कि सैन्य अधिकारियो को बड़े पद दिए गए हैं, जिससे वह प्रसन्न हैं। आईआरआइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसी तरह से आवामी लीग सत्ता पर जमी हुई है। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी का पैंतरा भी आईआरआइ आजमाना चाहती थी लेकिन उसे यह लम्बी रेस का घोड़ा नहीं लगी। आईआरआइ ने पाया कि बीएनपी पर हुई कार्रवाइयों ने उसकी छवि खराब कर दी है। बांग्लादेश के आम लोग उसे पसंद नहीं करते। इसके अलावा आईआरआइ ने यह भी कहा कि बीएनपी में दो गुट चल रहे हैं जिनमे से एक ढाका जबकि दूसरा लंदन से चलता है। ऐसे में आईआरआइ ने सत्ता परिवर्तन के लिए बीएनपी को फिट नहीं समझा। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद युनुस को इसीलिए लाया गया क्योंकि बीएनपी मुखिया खालिदा जिया की अब भी स्वीकार्यता नहीं है। आईआरआइ चाहती थी कि बांग्लादेश में कोविड महामारी में बड़ा नुकसान हो जिसका फायदा उठा कर शेख हसीना का तख्तापलट किया जाए। आईआरआइ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, कोरोनावायरस महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों से बांग्लादेश की राजनीति अस्थिर होने की संभावना थी। हालाँकि, बांग्लादेश में मृत्यु दर कम रही और खतरनाक अनुमानों के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इस तरह आईआरआइ के हाथ से यह एक मौका भी चला गया।

अमेरिकी एजेंसी आईआरआइ को मात्र बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार या उनकी पार्टी आवामी लीग से ही नहीं बल्कि भारत से भी समस्या है। आईआरआइ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, बांग्लादेश में राजनीति में दो दलों का वर्चस्व है अवामी लीग (एएल) और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी )। पिछले दस सालो से, भारत के समर्थन के कारण आवामी लीग लगातार आधिपत्यवादी, राजनीतिक मुकाबले पर हावी होने वाली और भ्रष्ट हो गई है।

आईआरआइ ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में भारत का प्रभाव कम करने की जरूरत है। एक अन्य रिपोर्ट में आईआरआइ ने कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि आवामी लीग और शेख हसीना भारत के समर्थन के तहत किसी भी तरह से फिर से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के भीतर इस इलाके की शक्तियों (भारत और चीन) के हस्तक्षेप को संतुलित करना आवश्यक है। आईआरआइ ने यह भी बताया कि उसने बीएनपी हो या अवाम्मी लीग, दोनों में बड़े स्तर पर घुसपैठ कर ली थी। इसके लिए उनसे पाँच अमेरिकी राजनयिकों का सहारा लिया था। इनमे से एक यूएसएआईडी में तैनात था। इस पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड लू समेत बाकी अधिकारी देख रहे थे। आईआरआइ की गतिविधियाँ जहाँ एक तरफ चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना लगातार इस खतरे को समझ रहीं थी। अप्रैल, 2023 में बांग्लादेश की संसद में हसीना ने इसी खतरे को लेकर देश को आगाह किया था।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

कल्पमेधा

किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है।
- वाल्तेयर

## आखिर समझौता

कोलकाता प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या मामले में आखिरकार सरकार और प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के बीच समझौता हो गया है। मंगलवार को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी। उसके पहले रात को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की सारी मांगें मान लीं। फिर सुप्रीम कोर्ट में कनिष्ठ चिकित्सकों ने काम पर लौटने को लेकर सहमति जता दी। निस्संदेह यह बड़ी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और सीबीआइ से जांच कराने का आदेश दिया था। मंगलवार को सुनवाई में अदालत के तीन जजों की पीठ ने कहा कि वे सीबीआइ की जांच से संतुष्ट हैं और उसमें कई महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। करीब हफ्ता भर पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की थी। मगर वे काम पर नहीं लौटे। अब उनसे बातचीत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसी भी कनिष्ठ चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हालांकि ममता बनर्जी कहती रही हैं कि इस मामले में जो भी कठोर कदम हो सकते हैं, उनकी सरकार उठाएगी। सीबीआइ जांच का प्रस्ताव भी उन्होंने शुरू में ही रख दिया था। कुछ अस्पताल कर्मियों और पुलिस कर्मियों को तभी निलंबित कर दिया गया था। जांच में तथ्यों के मुताबिक कुछ पूर्व अस्पताल कर्मियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा गया। अब प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों की मांग पर पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग के दो निदेशकों को भी हटा दिया जाएगा। चिकित्सकों की सुरक्षा के मद्देनजर अस्पतालों में उनके विश्राम स्थल को सुविधाजनक बनाने, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने जैसे कुछ उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पतालों में निगरानी समिति और शिकायत निवारण समिति के गठन पर भी सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल सरकार बलात्कार के मामले में कानून को पहले ही सख्त बना चुकी है। इस तरह लंबे समय तक बाधित रहे अस्पतालों के कामकाज में अब गति आ सकने की स्थिति बनी है।

दरअसल, कोलकाता प्रशिक्षु चिकित्सक प्रकरण इसलिए भी लंबे समय तक उलझा रहा कि उसे सियासी रंग दे दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार प्रदर्शनकारियों के हक की सुरक्षा करते हुए उनसे बातचीत करने की अपील तो करती रही, मगर वे काफी समय तक बातचीत की मेज पर नहीं आए। इस तरह अस्पतालों का कामकाज बाधित रहा, मरीजों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरू में कोलकाता के चिकित्सकों के समर्थन में देश के विभिन्न हिस्सों में डाक्टर हड़ताल पर चले गए थे, उससे व्यापक समस्या पैदा हो गई थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय की अपील पर कोलकाता को छोड़ कर बाकी जगहों के चिकित्सक वापस काम पर लौट गए थे। दरअसल, चिकित्सकों के काम पर न लौटने का खमियाजा नाहक मरीजों को भुगतना पड़ता है। बहुत सारे नाजुक स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान पर बन आती है। इसलिए कोशिश यही थी कि वे काम पर लौटें। हालांकि चिकित्सकों के रोष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें अनेक विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय भी उन स्थितियों से वाकिफ है और कई मौकों पर राज्य सरकारों को उन्हें सुधारने का निर्देश दे चुका है। कोलकाता प्रकरण में हुए समझौते दूसरे अस्पतालों के लिए भी नजीर बनेंगे।

## मनमानी के विरुद्ध

किसी गैरकानूनी गतिविधि या अपराध का आरोप झेल रहे व्यक्ति के घर या अन्य निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कथित 'बुलडोजर न्याय' के मसले पर जो राय जाहिर की है, वह राज्य सरकारों और संबंधित महकमों के लिए विचार करने का विषय है। यह बड़ी विडंबना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के बजाय अन्य कारणों का हवाला देकर उसका घर ढहा दिया जाए। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अक्तूबर तक के लिए देश भर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी और कहा कि बिना उसकी अनुमति के एक भी निर्माण न ढहाया जाए। हालांकि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

दरअसल, पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर महज आरोप लगने के बाद उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त करना एक जरूरी कार्रवाई मान ली गई थी। जबकि ऐसी कार्रवाई को मनमाने तौर-तरीके और उसके महिमामंडन के रूप में देखा जा रहा था। इसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई का महिमामंडन बंद करने को कहा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता का कहना था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। गौरतलब है कि बुलडोजर चलाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक व्यक्ति के सिर्फ आरोपी या यहां तक कि दोषी होने के बावजूद इस वजह से उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। एक लोकतांत्रिक और कानून के शासन वाले देश में किसी एक शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को उसके घर को ध्वस्त करके नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। संभव है कि किसी घर को अवैध निर्माण होने या अन्य तकनीकी आधार पर ध्वस्त किया गया हो, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई की तात्कालिक वजह आपराधिक कृत्य में आरोपी होना प्रतीत हो रही हो, तो उसे कैसे देखा जाएगा!

# दुविधा में झूलते अमेरिकी मतदाता

**राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और उलझन भरी बातें हुईं। उससे पता चला कि हैरिस और ट्रंप दोनों की ही, घरेलू और वैश्विक संदर्भ में बड़े मुद्दों को संबोधित करने में शायद कोई रुचि नहीं है।**



अरविंद कुमार

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। पिछले दिनों डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच नब्बे मिनट की चुनावी बहस हुई। मगर उस बहस से अमेरिकी मतदाताओं को किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद नहीं मिली और न चुनाव को लेकर कोई साफ तस्वीर सामने आ सकी। यह दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक गंभीर नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और उलझन भरी बातें हुईं। उससे पता चला कि हैरिस और ट्रंप दोनों की ही, घरेलू और वैश्विक संदर्भ में बड़े मुद्दों को संबोधित करने में शायद कोई रुचि नहीं है। अमेरिका अभी आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जहां मुद्रास्फीति बहुत अधिक है और बढ़ती बेरोजगारी असहनीय होती जा रही है। मगर इसके बावजूद, दोनों की बहसों से स्पष्ट रूप में यही लगा कि न तो हैरिस और न ही ट्रंप के पास, इन मुद्दों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक योजना पर चर्चा करते हुए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई का उल्लेख किया और कहा कि जब वे वार्टन स्कूल आफ फाइनेंस में गए थे, तब सभी शीर्ष प्रोफेसरों ने उनकी योजना को शानदार बताया था। मगर यह समझ से परे है कि वे दर्शकों के सामने अपनी योजना का विवरण क्यों नहीं दे सके। वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में, दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से में किसी न किसी तरह का संघर्ष चल रहा है। मगर हाल के दिनों में अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाइयों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शांति और स्थिरता लाने में शायद उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और इजराइल-हमास संघर्ष से इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि अमेरिका अब वैश्विक मामलों का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है।

कमला हैरिस ने दावा किया कि ट्रंप आसानी से यूक्रेन को रूस के हवाले कर देंगे। यह किसी भी रूप में अच्छा विचार नहीं था। हालांकि इजराइल को लेकर हैरिस की स्थिति पर ट्रंप के दावे भी उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं और अगर वे राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो दो साल के भीतर इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये कटाक्ष अमेरिकी मतदाताओं और बाकी दुनिया को यह एहसास नहीं करा पाए कि अमेरिका किस ओर जा रहा है। हैरिस ने जो सबसे बुरा काम किया, वह था ट्रंप के अहं पर सीधा हमला। उन्होंने कहा कि विश्व के नेता और अमेरिकी जनरलों को लगता है कि ट्रंप 'विध्वंसक' हैं। उन पर जवाबी हमला करते हुए ट्रंप ने हैरिस को 'मार्क्सवादी' बताया और



पिछले चार वर्षों के कुशासन के लिए उन्हें दोषी ठहराया।

आप्रवासन को लेकर ट्रंप के विचार किसी से छिपे नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के पूरे चार सालों में वे इसी बात पर बहस करते रहे कि अमेरिका-मैक्सिकन सीमा पर दीवार खड़ी

> जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि ट्रंप पूरी तरह तैयारी करके नहीं आए थे। इसीलिए वे निश्चित रूप से घरेलू और वैश्विक चिंता से जुड़े कई क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन की विफलताओं को लेकर हैरिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। हालांकि ट्रंप के पास निश्चित रूप से अच्छी बहस करने का कौशल है, इसलिए उम्मीद थी कि वे एक सुसंगत और सटीक विचार के साथ सभी को परास्त कर देंगे। दूसरी ओर, हैरिस लगातार ट्रंप को उनकी केंद्रित सोच से दूर करने के लिए उकसाती रहीं। हैरिस ऐसा रणनीतिक रूप से जानबूझकर करती रहीं और वे ब्योरों की तरफ से ट्रंप का ध्यान भटकाने में सफल भी रहीं।

की जाएगी और अवैध वे आप्रवासियों के प्रवाह को रोकेंगे। वह बात दुनिया भर में बहस का मुद्दा बन गई थी। आप्रवासियों को लेकर उनका सख्त रुख डेमोक्रेट्स के दृष्टिकोण के बिल्कुल उलट है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंद्रहवीं शताब्दी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तभी से अमेरिका आप्रवासियों का देश बना हुआ है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अवैध आप्रवासी ओहियो और कई अन्य जगहों पर पालतू जानवरों को मार कर खा रहे हैं।

जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि ट्रंप पूरी तरह तैयारी करके नहीं आए थे। इसीलिए वे निश्चित रूप से घरेलू और वैश्विक चिंता से जुड़े कई क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन की विफलताओं को लेकर हैरिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। हालांकि ट्रंप के पास निश्चित रूप से अच्छी बहस करने का कौशल है, इसलिए उम्मीद थी कि वे एक सुसंगत और सटीक विचार के साथ सभी को परास्त कर देंगे। दूसरी ओर, हैरिस लगातार ट्रंप को उनकी केंद्रित सोच से दूर करने के लिए उकसाती रहीं। हैरिस ऐसा रणनीतिक रूप से जानबूझकर करती रहीं और वे ब्योरों की तरफ से ट्रंप का ध्यान भटकाने में सफल भी रहीं।

सवाल-जवाब के क्रम में वैसे तो हैरिस से पूछा गया पहला सवाल सीधा था, लेकिन वे उस पर टालमटोल करती रहीं और जिस तरह के जवाब की अपेक्षा थी, वह नहीं दे पाईं। हैरिस से पूछा गया था कि 'क्या आपको लगता है कि चार वर्ष पहले अमेरिकी नागरिक जिस स्थिति में थे, अब उससे बेहतर स्थिति में हैं?' इस सवाल का जवाब 'हां' या 'नहीं' में देने के बजाय उन्होंने इस मुद्दे पर बात की कि वे अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाएंगी। पिछले चार वर्षों में निश्चित रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। मगर, हैरिस के पास आज के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी और उन्होंने अमेरिकी लोगों के लिए एक सुनहरे कल का सपना पेश किया।

गर्भपात, बंदूक कानून और विश्व नेताओं की धारणा जैसे कई अन्य मुद्दों पर बहस किसी भी निष्पक्षता के साथ नहीं होती दिखी। गर्भपात पर हैरिस ने वादा किया कि जब कांग्रेस 'रो बनाम वेड' के सुरक्षा उपायों को वापस लागू करने के लिए विधेयक पारित करेगी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वे बड़े गर्व के साथ उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानूनी रूप देंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूकों के प्रसार पर निश्चित रूप से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दोनों उम्मीदवारों के बारे में विश्व नेताओं की धारणा अभी विकसित होनी बाकी है। मगर, बाकी दुनिया के साथ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की निकटता के बारे में सबको पता है।

जहां तक भारत का सवाल है, उनके द्विपक्षीय दृष्टिकोण में निरंतरता बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करेगा और उन जिम्मेदारियों में हाथ बंटाएगा, जहां भारत वैश्विक मामलों का नेतृत्व करने में बड़ी भूमिका निभाने को आगे बढ़ेगा।

अमेरिकी मतदाता दुविधा में हैं, बाकी दुनिया भी दुविधा में है। चुनावी बहस को लेकर एबीसी न्यूज तटस्थ नहीं रह सका और हैरिस के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को खुलकर प्रदर्शित किया। जाहिर है, चुनावी संघर्ष की दृष्टि से पेंसिल्वेनिया और विस्कान्सिन तथा फिलाडेल्फिया और मिल्वौकी जैसे प्रमुख जनसंख्या बहुल महत्त्वपूर्ण राज्य निर्णायक साबित होंगे। अन्य दो पश्चिमी राज्य- एरिजोना और नेवादा भी आगामी राष्ट्रपति चुनाव के समग्र परिणामों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

*(लेखक स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू में प्रोफेसर हैं।)*

# मित्रता की परिधि

पल्लवी सिंह

मित्रता एक ऐसा विषय है, जो इस समाज के लिए सबसे ज्यादा विचार का मामला रहा है और यह ऐसा विषय भी रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा लिखा गया है। फिर भी समय के साथ इसके अलग-अलग रूप का सामना करते हुए इस पर विचार करने, सोचने का आग्रह कई बार हावी हो जाता है। दरअसल, मित्रता मानव जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान धरोहरों में से एक है। यह केवल सामाजिक संबंधों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मीयता के अद्वितीय अनुभवों का स्रोत भी है। मित्रता विश्वास, समर्पण और निश्छल प्रेम की डोर से बंधी होती है, जो जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य दे जाती है। इसके अभाव में मनुष्य मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है, क्योंकि यह जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है, जिन्हें अन्य किसी भी संबंध में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

इस संदर्भ में यह टिप्पणी अहम है कि मित्रता की परीक्षा विपत्ति में दी गई मदद से होती है और वह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए। यह कथन मित्रता के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। विपत्ति के क्षणों में, जब जीवन अंधकारमय और निराशाजनक प्रतीत होता है, एक सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर सामने आता है। वह तन, मन और धन से अपने मित्र की सहायता करता है और उसे विपत्ति के गहरे गर्त से बाहर निकालता है। ऐसी स्थिति में मित्रता का वास्तविक मूल्य और उसकी गहनता स्पष्ट रूप से सामने आती है।

## दुनिया मेरे आगे

> हम सभी अपने जीवन में एक ऐसे सच्चे और अच्छे मित्र की तलाश में रहते हैं, जो हमारे जीवन के कठिन समय में हमारा साथ दे, हमारी बातों को समझे और हमारे सुख-दुख में समान रूप से भागीदार बने। यह वह संजीवनी है, जो हमें सभी रिश्तों और संकोच से ऊपर उठाकर अपने मित्र के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने की स्वतंत्रता देती है।

हालांकि, मित्रता को निभाना जितना कठिन है, उतना ही यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में मित्रता का अर्थ और उद्देश्य बदलता जा रहा है। दरअसल, आजकल कई मामलों में यह देखा जा सकता है कि मित्रता का उपयोग केवल स्वार्थ साधने के लिए किया जाता है। लोग केवल अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं और समय पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में मित्रता की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाता है। अरस्तू ने सही ही कहा है कि 'मित्रों के बिना कोई भी जीना पसंद नहीं करेगा, चाहे उसके पास बाकी सब अच्छी चीजें क्यों न हों।' सच यह है कि मित्र जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो इसकी समृद्धि और संपन्नता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हम सभी अपने जीवन में एक ऐसे सच्चे और अच्छे मित्र की तलाश में रहते हैं, जो हमारे जीवन के कठिन समय में हमारा साथ दे, हमारी बातों को समझे और हमारे सुख-दुख में समान रूप से भागीदार बने। यह वह संजीवनी है, जो हमें सभी रिश्तों और संकोच से ऊपर उठाकर अपने मित्र के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने की स्वतंत्रता देती है। यह, जो हमें सही दिशा दिखाए, न कि हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के नाम पर हमारी गलतियों को अनदेखा करे। मित्रता का असली मापदंड यही है कि हमारा मित्र हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे और गलतियों पर हमें सही दिशा दिखाए।

संगति का प्रभाव व्यक्ति के गुणों और उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है। अच्छी संगति से व्यक्ति के गुणों में निखार आता है, जबकि बुरी संगति से ये गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को भी अच्छी संगति का चयन करना चाहिए। यह जगजाहिर तथ्य है कि मित्रता का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल हमारे चरित्र को निखारती है, बल्कि हमारे जीवन के निर्णयों और सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती है। जैसे सुगंधित वस्त्रों से सज्जित शरीर, वैसे ही उत्तम मित्रता से सजा हुआ मनुष्य का व्यक्तित्व। इसके विपरीत, बुरी संगति मनुष्य को पतन की ओर धकेल सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने मित्रों का चयन अत्यंत सावधानी और विवेकपूर्वक करें, ताकि उनकी संगति से हमारे व्यक्तित्व को निखार मिले और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

मित्रता का मूल्यांकन केवल इसके स्थायित्व और समर्थन में नहीं है, बल्कि इसमें भी है कि यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही तरीके से अपनाने में मदद करती है। मित्रता का असली स्वरूप तब प्रकट होता है, जब हम अपने मित्रों के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और एक दूसरे के जीवन को समृद्ध करते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित करती है, बल्कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। सच यह है कि मित्रता का मूल्यांकन उसके प्रभाव, योगदान और समर्थन के आधार पर किया जाना चाहिए। यह जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है, जिन्हें अन्य किसी भी संबंध में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हम इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं और इसे अपनी सोच, विचारधारा और कार्यों में अभिव्यक्त करते हैं।

मुश्किल यह है कि आज तेज रफ्तार से भागती-दौड़ती जिंदगी में मित्रता को भी सतही अर्थों में लिया जाने लगा है। ऐसे उदाहरण हमारे आसपास बिखरे पड़े होंगे, जिनमें कोई व्यक्ति मित्रता के नाम पर महज काम का संबंध निभाता है और मित्र की जरूरत के वक्त किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने से मुकर जाता है। भावनाओं से रिक्त संबंधों को जान-पहचान के तौर पर भले देखा जाए, उसे मित्रता नहीं कहा जा सकता।

## उपयोग बनाम जोखिम

प्लास्टिक ने बहुमुखी उपयोग, टिकाऊपन और कम लागत के चलते पैकेजिंग, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और इलेक्ट्रानिक्स में व्यापक पहुंच बनाई है। प्लास्टिक उत्पादों ने खाद्य संरक्षण में सुधार किया है, परिवहन लागत को कम किया है और चिकित्सा प्रगति को सक्षम किया है। हालांकि प्लास्टिक के व्यापक उपयोग ने महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा की हैं। अधिकांश प्लास्टिक गैर-बायोडिग्रेडेबल है, जिससे लैंडफिल और महासागरों में लंबे समय तक प्रदूषण होता है। समुद्री जीवन को नुकसान होता है, क्योंकि जानवर प्लास्टिक कचरे को निगलते हैं या उसमें फंस जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य शृंखलाओं में प्रवेश किया है, जो संभवतः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की सुविधा ने 'इस्तेमाल करो और फेंको' की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। हालांकि पुनर्चक्रण प्रयासों में वृद्धि हुई है, वे प्लास्टिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने के लिए संघर्ष करते हैं। प्लास्टिक के लाभों को उसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संतुलित करना समाज के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

*- चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम*

## सक्रियता से सेहत

शारीरिक गतिविधि अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मगर यह ऐसे समय में अधिक सच नहीं हो सकती, जब युवा अधिकतम स्क्रीन समय के साथ इलेक्ट्रानिक संयंत्रों का उपयोग करते हैं और बाहरी मनोरंजक गतिविधियों में कम समय बिताते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि भारतीय अपने पड़ोसियों या अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में स्वस्थ और चुस्त होने के पैमाने में भी स्थान नहीं रखते हैं। आमतौर पर वयस्कों को सप्ताह में डेढ़ सौ मिनट और बच्चों और किशोरों को प्रतिदिन साठ मिनट की गतिविधि की आवश्यकता होती है। महिलाओं का अधिकतम समय देखभाल या घरेलू कामों में व्यतीत होता है, जिससे वे शारीरिक गतिविधि के प्रति संवेदनशील होती हैं। जरूरी यह है कि गतिहीन जीवन को खराब स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, खासकर शहरी क्षेत्रों में, जहां कई परिवार खुद को चारदीवारी तक सीमित रखते हैं। गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करने की जरूरत है।

*- विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल*

## बीमा में राहत

वर्तमान समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा साधारण जनता के लिए अत्यधिक महंगा होता जा रहा है, जिससे लोग पर्याप्त बीमा सुरक्षा लेने से हिचकिचा रहे हैं। अस्पतालों के बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए एक सुदृढ़ बीमा पालिसी लेना आवश्यक लगने लगा है, मगर अठारह फीसद जीएसटी का कर भार इस दिशा में एक बड़ी अड़चन साबित हो रहा है। हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका, हालांकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कटौती की मांग पर विचार किया जा रहा है। देश में सीमित स्वास्थ्य सेवाओं के चलते एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को गहरे आर्थिक संकट में धकेल सकती है। इसलिए सरकार को केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी पालिसीधारकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि इससे आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके।

*- अशोक भास्कर श्रीवास्तव, लखनऊ*

## तोहफे का सिरा

भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में मुफ्तखोरी का दुश्चक्र व्यापक हो चुका है। सरकारों को चाहिए कि वे मुफ्त तोहफे देने के बजाय लोगों को सक्षम और समर्थ बनाएं, ताकि वे स्वयं जीविका चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर सकें। मुफ्त सामग्री वितरण योजनाओं से अधिक जरूरी वंचितों की शिक्षा और आर्थिक सक्षमता सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमें स्कूलों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विकास करना होगा। पढ़ाई के साथ ही विद्यार्थियों को लघु उद्योग या दूसरे व्यवसायों का प्रशिक्षण देना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा कि अगर मनुष्य की श्रम शक्ति का सदुपयोग नहीं किया गया तो राष्ट्रीय उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वर्तमान समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना और उनके श्रम का सही उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए।

*- अमित पांडेय, बिलासपुर, छग*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दैनिक जागरण

पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आशीर्वाद की वर्षा करती है

# एक साथ चुनाव की तैयारी

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह यह स्पष्ट किया कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का परिचय एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित समिति से भी मिला था। इस समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में उन बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए हैं, जो एक साथ चुनाव कराने में आड़े आ सकती हैं। यह रिपोर्ट यही बताती है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे तर्क खोखले ही अधिक हैं। ये तर्क इसलिए भी खोखले साबित होते हैं कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। आखिर इस तथ्य के आलोक में यह कैसे कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराना संविधानसम्मत नहीं? क्या जब एक साथ चुनाव होते थे तो वे संविधान की उपेक्षा करके होते थे? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब भी लोकसभा के साथ कुछ विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इस बार लोकसभा के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव हुए। आखिर जब लोकसभा के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो शेष राज्यों के क्यों नहीं हो सकते? वास्तव में यह दलील विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का ही परिचायक है कि एक साथ चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं।

एक साथ चुनाव केवल इसलिए नहीं होने चाहिए कि देश को बार-बार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। ये इसलिए भी होने चाहिए, ताकि संसाधनों की बचत के साथ चुनावी माहौल के कारण पैदा होने वाली अनावश्यक राजनीतिक कटुता से बचा जा सके। बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। इससे विकास एवं जनकल्याण के काम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव में यदि कुछ बाधक है, तो वह है राजनीतिक संकीर्णता। राष्ट्रहित में इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए। क्या ऐसे देशों को कम लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, जहां संसद के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं? यह ठीक नहीं कि एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों को अपनाने से भी बच रहे हैं। समय की मांग तो यह है कि उन्हें न केवल एक साथ चुनाव पर सहमत होना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाने पर भी राजी होना चाहिए, जिसमें प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की भी भागीदारी हो। अभी तो प्रत्याशी चयन में मनमानी ही होती है। हालांकि इसके दुष्परिणाम राजनीतिक दल ही भोगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे प्रत्याशी चयन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाना चाहते?

# 'चीता युग' के दो वर्ष

दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के दिल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़कर भारत में एक नए 'चीता युग' की शुरुआत की थी। विलुप्त हो चुके बिल्ली प्रजाति के इस आकर्षक प्राणी की करीब 75 वर्ष बाद देश में आमद हुई। भारत के वातावरण से सामंजस्य बैठाने और विदेशी धरती के इस जीव के देशी हो जाने पर लगातार होती बहस के बीच यह स्वर्णिम अध्याय रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आया। परिस्थितिजन्य सामंजस्य और मौसमी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में लगे समय में कुछ चीते काल-कवलित हो गए, तो कुछ ने अपना वंश बढ़ाकर चीता प्रोजेक्ट के सफल होने पर मुहर भी लगा दी। वर्ष 1972 से चल रहीं चीतों को भारत लाने की कोशिशें आखिरकार वर्ष 2022 में जाकर सफल हुईं। 1973 में पहली बार भारत और ईरान सरकार के बीच अनुबंध हुआ था, लेकिन बात नहीं बन सकी। 2008 में दोबारा इस परियोजना को लेकर प्रयास हुए, लेकिन अंततः यह मसला 2020 में सुलझाया जा सका। 2022-23 में नामीबिया से आठ और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से आठ वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। इन चीतों के वंश में जन्मे 17 शावकों में से 12 जीवित हैं। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि अभी 'चीता युग' शैशव अवस्था में ही है। देश को चीतों की गौरव भूमि का स्थान प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा तय करना होगी। चीतों की रफ्तार पर सवार होकर पर्यटन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का स्वप्न भले ही बेहद सुखद हो, लेकिन इस राह की चुनौतियों से जूझना भी कम मुश्किल नहीं है। हाल ही में हुई चीता पवन की मौत के बाद पार्क प्रबंधन के साथ ही चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों ने सतर्कता का दायरा और विस्तृत किया है। यही वजह है कि चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने को लेकर अब भी अधिकारी निश्चिंत नहीं हैं।

# सिकुड़ता गरीबी का दायरा



विवेक देवराय

**भोजन में बढ़ती विविधता, आमदनी में वृद्धि और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है**



आदित्य सिन्हा



अवधेश राजपूत

गरीबी के मुद्दे पर लंबे समय से गंभीर बहस होती आई है। इस बहस का एक बिंदु यह भी होता है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या असर पड़ता है। अमूमन यही माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि के विस्तार के साथ ही गरीबी का दायरा सिकुड़ता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक न्यूनतम कसौटी को गरीबी रेखा के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त आमदनी के आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय नहीं तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खपत को पैमाना माना गया है। पिछली सदी के छठे दशक में विकसित हुई इस पद्धति को आठवें दशक में संशोधित किया गया।

गरीबी के आकलन में सटीक डाटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम गरीबी रेखा को भलीभांति रूप से परिभाषित करना भी है। इस कड़ी में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी एचसीईएस अहम भूमिका निभाता है। इस सर्वे में खानपान, परिधान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। एचसीईएस के हालिया आंकड़ों में गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दशा-दिशा को दिखाते हैं। इससे जुड़े आंकड़ों के दूसरे चरण की जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है। उनके सामने आने के बाद हमें कुछ और ठोस आधार मिलेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके व्यापक विश्लेषण से देश में उपभोग के रुझान को लेकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग अब केवल अनाज पर ही केंद्रित न होकर अपने भोजन में दूध, मांस, फल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी तरजीह दे रहे हैं। खानपान के रुझान में इस परिवर्तन का कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य और जनकल्याण जैसे पहलुओं से गहरा सरोकार है। इस रुझान के प्रमुख निष्कर्षों की पड़ताल करें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण उपभोग में 164 प्रतिशत तो शहरी उपभोग में 146 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जबरदस्त तेजी दिखाई। ग्रामीण सिक्किम 394 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर काबिज रहा। इसका दूसरा पहलू तो और भी महत्वपूर्ण है और वह यह कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भोजन सामग्री पर घरेलू खर्च का हिस्सा 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है। भोजन पर होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ ही एंगेल के नियम के अनुरूप भी है कि आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता जाता है। तीसरा पहलू, अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी पर मौजूद 20 प्रतिशत लोगों के स्तर पर यह देखने को मिला है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य सुरक्षा पहल की भी भूमिका हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। इसके चलते लोग अपने भोजन में फल, सब्जियां, डेरी उत्पाद और एनिमल प्रोटीन शामिल कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, जो नीतियां अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि हमारी कृषि नीतियों की दिशा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए।

मौजूदा व्यवस्था में गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कायम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और खरीदारी से जुड़ा तंत्र इनकी मांग घटने के बावजूद उनके उत्पादकों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। ऐसे में बागवानी, डेरी और मवेशियों पर जोर देना टिकाऊ एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने के साथ ही कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चे को भी मजबूत करेगा। यह रिपोर्ट कुछ चिंताजनक पहलुओं की ओर संकेत करती है। ऐसा ही एक पहलू प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बेतहाशा बढ़ते उपभोग का है। खासतौर से शीर्ष 20 प्रतिशत अमीर आबादी में यह खपत खासी बढ़ी है, जिससे जनस्वास्थ्य के समक्ष एक संकट आकार ले रहा है। तमाम शोध-अनुसंधान निरंतर रूप से यह दर्शाते हैं कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और मोटापा, मधुमेह एवं हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर-संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध है। ऐसे में, सरकार को इन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लेकर पोषण से जुड़े पहलुओं के विनियमन का कोई उपाय करना चाहिए। साथ ही, इन खाद्य सामग्रियों के अतिशय उपभोग को लेकर जनजागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है। विशेष रूप से शहरी इलाकों में ऐसा किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी संकेत करती है। जैसे एनीमिया के बढ़ते मामले। इस लिहाज से महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। सरकार द्वारा आयरन युक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बावजूद एनीमिया की समस्या बनी हुई है। ऐसे में केवल आयरन युक्त खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि खानपान में विविधता भी एनीमिया की चुनौती से निपटने में उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है, जो विविधतापूर्ण, पोषण से परिपूर्ण भोजन तक पहुंच को सुगम बना सकें। विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यक है। उपभोग का यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

यदि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी अनुसार संशोधित की जाए। तभी महंगाई की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। कुल मिलाकर, भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है। हमें अपनी नीतियों को भी बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो हमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण के मोर्चे पर चुनौतियों का भी तोड़ निकालना होगा।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

# उनकी भी सुनें, जिनकी सुनवाई नहीं



राजीव सचान

**एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने की मांग करने वालों की अनदेखी उचित नहीं**



एससी-एसटी कोटे में उपवर्गीकरण का समर्थन। फाइल

इससे सभी भली तरह परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई दलों और संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है कि एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करना संविधानसम्मत है, लेकिन आखिर इससे कितने लोग अवगत हैं कि इस फैसले का स्वागत करने वाले भी हैं। इनमें मुख्यतः एससी-एसटी समाज की वंचित जातियों के संगठन हैं। वंचित जातियों के ये संगठन एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का स्वागत करने के साथ ही उसे लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कठिनाई से ही सुनी जा रही है, क्योंकि कोई प्रमुख दल या संगठन उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। उत्तर भारत में ले-देकर जीतनराम मांझी का दल ही एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहा है। मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर जैसे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारत बंद के जरिये सड़कों पर उतरकर नाराजगी भी जताई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में भी कई संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता मीडिया के एक बड़े हिस्से में दर्ज ही नहीं हो पा रही है।

इसी 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने अशोक अज्ञानी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर सत्याग्रह किया, लेकिन इसकी जानकारी शायद ही किसी को हुई हो। इसी तरह झालावाड़ में राजस्थान समग्र भील वर्ग ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर अरविंद भील के संयोजन में एक बड़ा जुलूस निकाला। इसमें करीब 25 हजार लोग शामिल हुए, लेकिन वह स्थानीय मीडिया में ही दर्ज होकर रह गया। यही स्थिति अन्य अनेक शहरों में हुए आयोजनों को लेकर रही। एससी-एसटी समाज की वंचित जातियों के छोटे-बड़े संगठन ऐसे आयोजन अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर न तो जनता का ध्यान जा रहा है और न ही सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक दल पहले कभी एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन किया करते थे, उन्होंने या तो चुप्पी साध ली है या फिर अपने रुख को स्पष्ट करने से इन्कार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस पर हम मंत्रणा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत किया था। इस फैसले का स्वागत करने वालों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन चिराग पासवान इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं।

एक-दो क्षेत्रीय दलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं या मौन धारण किए हैं। विरोध करने वाले यह तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एससी-एसटी समाज की एकता खत्म करने वाला है। आखिर यह कैसी एकता है, जिसमें एससी-एसटी समाज के हितों की चिंता करने वाले ही यह देखने को तैयार नहीं कि उनके बीच आरक्षण के लाभ से वंचित जातियां भी हैं। इन दोनों वर्गों की वंचित जातियों के कई संगठन एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने के भी पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आवश्यकता भर जताई है और दूसरे राजनीतिक कारणों से कोई भी और यहां तक कि केंद्र सरकार भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं। अधिकांश दल यह कहते हुए इसके विरोध में आ गए हैं कि संविधान में क्रीमी लेयर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यदि ऐसा है तो ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे लागू है?

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि उच्च पदों पर पहुंच गए एससी-एसटी समाज के लोगों से भी भेदभाव होता है। इससे इन्कार नहीं, लेकिन इसका अर्थ है कि आरक्षण पिछड़े तबकों के उत्थान का जरिया भले हो, उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने का कारगर उपाय नहीं। स्पष्ट है कि भेदभाव को दूर करने के लिए केवल आरक्षण पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। इसे दूर करने के लिए सरकारों और समाज को कुछ और करना होगा। इसके लिए एससी-एसटी समाज की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां और इस समाज के हितों की बातें करने वालों को भी सक्रिय होना होगा, क्योंकि यह एक सच्चाई है कि एससी-एसटी समाज की वंचित जातियों से इन वर्गों की वे जातियां भी दूरी बनाकर रखती हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और जो राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि जब एससी-एसटी समुदाय की वंचित जातियों के संगठन आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने पर बल देने के लिए अपने कार्यक्रमों में लोगों के आने की अपील कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले दलों और संगठनों के समर्थक एक्स, फेसबुक आदि प्लेटफार्म पर उन पर तंज कस रहे थे और उन्हें इनका या उनका एजेंट बता रहे थे।

विडंबना यह है कि एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वाले वे भी हैं, जो यह नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी। भले ही ऐसे लोग एससी-एसटी वर्ग की एकता की कितनी भी दुहाई दें, सच यह है कि इन दोनों वर्गों में अनेक ऐसी जातियां हैं, जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं या फिर जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। यदि एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाता तो यह इन समुदायों की दर्जनों वंचित जातियों के साथ जानबूझकर किया जाने वाला अन्याय होगा।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### पितृयज्ञ

मानवता की पोषक होने से भारतीय संस्कृति धरती के सभी प्राणियों के योगक्षेम की चिंता करती है। इसकी सिद्धि के लिए मानव को साधक बनाकर पंचयज्ञों का विधान किया गया है, जिसमें चेतन ही नहीं जड़ पदार्थों का भी ध्यान रखा गया है। मनुष्य पर जन्म से ही देव, ऋषि, पितृ आदि पांच ऋणों का भार होता है। पंचयज्ञ इनसे मुक्ति के साधन हैं। इनमें पितृयज्ञ पितृऋण से मुक्ति का उपाय है। वेदों ने माता-पिता के आदर, सम्मान एवं सेवा के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का उद्घोष किया है। इसी भावना की सिद्धि हेतु भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विधान है, जिसमें श्राद्ध कर्म द्वारा उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा भाव प्रमुख होने से इसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से समर्पित भोगों को पूर्वज भाव रूप में ग्रहण करते हैं। स्थूल के समान सूक्ष्म जगत भी सत्य है, जिसे भाव जगत भी कहा जाता हैं। माता-पिता एवं गुरु स्थूल शरीर के न रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से हमेशा जीवित रहते हैं। उनका मार्गदर्शन संबल बनकर सदा हमारे साथ रहता है। अतः उनकी संतृप्ति के लिए तर्पण एवं दान आदि के द्वारा पितृयज्ञ संपादित करने का विधान है। स्वार्थपूर्ण भोगवादी संस्कृति में जीने वाले लोग भले ही श्राद्धकर्म में विश्वास न करते हों, किंतु दूरद्रष्टा भारतीय ऋषियों का चिंतन व्यापक होने से परार्थपरक है। इस प्रयोजन में दान आदि क्रियाओं से जल, थल और नभ में रहने वाले जीवों का आत्मा भी तृप्त हो जाता है।

पितृयज्ञ का मूल उद्देश्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धा तथा सबके अंतर्मन में दीन-दुखियों के प्रति दया भाव जागृत करना है। भारतीय संस्कृति का यह अनूठा भाव दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके माध्यम से सनातन संस्कृति के लोग अपने मृत पूर्वजों को भी जलांजलि देते हैं। पितृपक्ष, वस्तुतः वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है, जो हमें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखती है।

डा. सत्य प्रकाश मिश्र

# कीटनाशकों के दुष्चक्र में कृषि

सुधीर कुमार

**कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक खतरा बनकर उभर रहा है**

कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सात देशों-भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम- ने सामूहिक रूप से किसानों को 379 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता देने की पहल की है। इसका मकसद प्लास्टिक और कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त कृषि को प्रोत्साहन देना है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

कृषि क्षेत्र में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक खतरा बनकर उभर रहा है। हर साल विश्व में 12 अरब किलोग्राम कृषि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि प्लास्टिक का उपयोग ज्यादातर ग्रीनहाउस बनाने के लिए किया जाता है। वहीं 'प्लास्टिक मल्चिंग' विधि के तहत प्लास्टिक की पतली परत फसलों की पंक्तियों को ढकती है, ताकि उनकी जड़ों को सुरक्षित रखा जा सके और फसल उगने के दौरान खरपतवारों को रोका जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग छाया और सुरक्षात्मक जाल तैयार करने तथा सिंचाई उपकरणों में किया जाता है। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग के बाद पूरी तरह से एकत्रण और उसका दोबारा उपयोग या पुनर्चक्रण करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह खराब या गंदा हो जाता है। इसके व्यापक उपयोग से मिट्टी में बड़ी मात्रा में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जमा होने लगते हैं, जिससे मृदा एवं जलस्रोत दूषित होते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशक अपरिहार्य बनता जा रहा है। कृषि में कीटनाशकों के प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके विषैले प्रभाव से हर साल लगभग 11 हजार लोग मरते हैं। मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के अलावा फसलों पर प्रयोग के बाद इसके अंश वायुमंडल, वर्षाजल के साथ मिलकर जल स्रोतों और भूमि में मिलकर मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग चार अरब टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक सीधे संपर्क के कारण त्वचा एवं आंखों, श्वसन के जरिये फेफड़ों और उत्पादित खाद्य पदार्थों के जरिये मानव शरीर में प्रवेश करता है। साथ ही यह पारिस्थितिकी-तंत्र को प्रदूषित करता है। यह पशु-पक्षियों, सूक्ष्म जीवों और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक है।

बहरहाल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 29, ऊर्जा खपत के 30, भूमि उपयोग के 33, भूजल निष्कर्षण के 70 और वनों की कटाई के 75 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाना जरूरी है। यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

## जनगणना में तत्परता दिखाए सरकार

'जनगणना में देरी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में यह बताया गया है कि इससे जो आंकड़े सामने आएंगे, उनसे सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। ये आंकड़े उद्योग जगत और शोधार्थियों सहित नीति-निर्माताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। यह सवाल बिल्कुल उचित है कि जब कोविड महामारी के दौरान भी देश में कई विधानसभाओं के चुनाव सहित अन्य अनेक आयोजन होते रहे तब भी देश में जनगणना नहीं कराई गई। अब भी सरकार के कदम इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यह सवाल सबके मन-मस्तिष्क में कौंध रहा है। कुछ राजनीतिक दल जातीय गणना की मांग कर रहे हैं, मगर उनका वैसा जोर आम जनगणना को लेकर नहीं है। इससे यह बात साबित हो रही है कि हमारे राजनीतिक दल उन्हीं मुद्दों को धार देने में यकीन करते हैं, जिनसे उन्हें राजनीतिक लाभ की उम्मीद रहती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब जनगणना में देरी हुई हो। पूर्व में भी ऐसा हुआ है। इसके बावजूद जनगणना की राह में आने वाले अवरोध जितने जल्दी दूर किए जा सकें, उतना ही बेहतर होगा। जनगणना के मोर्चे पर सरकार को तत्परता दिखानी ही होगी।

मुकेश कुमार मनन, पटना

## बेजा बयानबाजी

गत दिनों राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को लेकर बयानबाजी की। ऐसा वह पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए जो

## मेलबाक्स

आरोप लगाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा तो सरकार तानाशाही की राह भी चल सकती है, जो कि लोकतंत्र के लिए भी उचित नहीं है और न ही आमजन के लिए, लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जो भी सरकार तानाशाही की राह चली है, उसे आमजन ने मतदान के जरिये सत्ता से भी हटाया है, जैसे कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक देश पर राज किया था, लेकिन जब देश को यह अहसास होने लगा कि इंदिरा गांधी तानाशाही की राह चलने लगी हैं तो आमजन ने मतदान के द्वारा सत्ता से हटाया। राहुल गांधी से सवाल है कि विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने से क्या होगा? क्या अमेरिका हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा? क्या राहुल गांधी को देश के मतदाताओं पर भरोसा नहीं है? क्या देश के लोकतंत्र को खतरे में बताने से कोई विदेशी निवेशक हमारे देश में आएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश का लोकतंत्र खतरे में लगता है तो उन्हें कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए आगे लाना चाहिए, जिस पर देश भरोसा करे या फिर खुद ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

## राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मतांतरण

छल-कपट से मतांतरण और लव जिहाद देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि जबरन मत परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर गंभीरता दिखानी चाहिए और इस मुद्दे पर बिना राजनीतिक भेदभाव के काम करना चाहिए, ताकि अशिक्षित, आदिवासी और अन्य लोग बलि का बकरा न बन जाएं। बहुत ही गलत है कि धर्म विशेष के लोग दुनिया के सबसे बड़े पंथनिरपेक्ष देश का गलत फायदा उठाकर देश में मतांतरण करवा रहे हैं और इसके लिए वे गरीबों और आदिवासी लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसा आखिर वे कर क्यों रहे हैं? अगर धर्म विशेष के लोग गरीबों या अन्य लोगों का कोई भला करना ही चाहते हैं, उनकी कोई किसी तरह की मदद करना चाहते ही हैं, तो वे मत परिवर्तन की शर्त क्यों रखते हैं? जो चंद धन-दौलत के लालच में आकर परिवर्तन करते हैं, वे यह सिद्ध कर देते हैं कि उन्हें धर्म से नहीं भौतिकतावाद से प्यार है।

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेंद्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

********

**83** प्रतिशत संख्या हिंदुओं की है उत्तराखंड की कुल आबादी में। वहीं इसमें मुस्लिमों की संख्या 13.9 प्रतिशत है, जबकि शेष जनसंख्या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की है।





अरविंद कुमार मिश्रा
लोक नीति विश्लेषक

आजकल

# जैविक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

**हाल में केंद्र सरकार ने बायो ई-3 नीति को मंजूरी दी है। जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे जेनेटिक्स, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान आदि से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीक से खाद्यान्न सुरक्षा के साथ दवाएं, उर्वरक, टीके एवं अक्षय ऊर्जा समेत अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता को टिकाऊ बनाने में मदद मिल रही है। इससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है**

जैव प्रौद्योगिकी से खुलेगी विकसित भारत की राह। प्रतीकात्मक

भारत अगले तीन साल में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम विकासशील से विकसित देश की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ दवाएं, उर्वरक, टीके एवं अक्षय ऊर्जा समेत अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता को टिकाऊ बनाना होगा। दैनिक जीवन में खपत होने वाली कई वस्तुएं रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होती हैं। इन वस्तुओं को बनाने में काफी मात्रा में संसाधनों का नियोजन होता है। जलवायु संकट के दौर में हमें ऐसे संसाधन विकसित करने होंगे, जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ऐसे में जैव प्रौद्योगिकी समावेशी विकास का सबसे कारगर उपक्रम बनकर उभरा है। इससे प्रयोगशाला में नए उत्पाद एवं वस्तुएं तैयार करने वाली जैविक प्रक्रिया विकसित की जाती है। जीवधारियों से प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद तैयार होते हैं। यह संसाधनों के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र की अद्यतन विधियां हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बायो ई-3 नीति को मंजूरी दी है। इससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के मुताबिक 2020 में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था का आकार 70.2 अरब डालर का था। 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 2.6 प्रतिशत रही। इस दशक के अंत तक यह हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे जेनेटिक्स, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान आदि से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में नई दवाएं, टीके और उपचारों का विकास किया जा रहा है। कृषि में जेनेटिक रूप से संशोधित प्रजातियां, जैव ईंधन जहां कृषि व्यवस्था में बदलाव लेकर आए हैं वहीं कई तरह के रसायन कागज, वस्त्र और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। विश्व जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और जैव ईंधन ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैव ईंधन ऊर्जा का टिकाऊ भविष्य है, जो बिना किसी प्रदूषण के स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। जैव ईंधन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के साथ-साथ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जैव ईंधन का मतलब पेड़-पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। जैव ईंधन को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। बायोफ्यूल बाजार में अमेरिका और ब्राजील की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यूरोपीय संघ उसके बाद आता है। भारत सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है, जिसके तहत सरकार 2025-26 तक एथेनाल युक्त 20 प्रतिशत पेट्रोल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

**खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा :** जैव प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक अनुप्रयोग खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में है। इसकी मदद से हम नई किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आई है। विश्व में मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का पांचवां हिस्सा नष्ट हो जाता है। ऐसे में इसे बचाने में जैव तकनीक काफी असरदार साबित हो रही है। देश में फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी रोकने के लिए इसकी श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना होगा। केंद्र सरकार ने एथेनाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। आज देशभर में ई-20 ईंधन की खपत बढ़ने से देश का तेल खर्च कम हुआ है। बायो ई-3 नीति के लागू होने से जैव एथेनाल उत्पादन के क्षेत्र में तकनीक एवं नवाचार सामने आएंगे। अनाज एवं खाद्य पदार्थों से तैयार होने वाला बायो एथेनाल जैव प्रौद्योगिकी की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में एक है। इसी तरह परिशुद्ध खेती के लक्ष्य को हासिल करने में रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कीटनाशक अहम हैं। इनका विकास जैव प्रौद्योगिकी पद्धतियों से किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन आर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फार नार्थ ईस्टर्न रीजन जैसी अनेक योजनाओं की सफलता में बायो ई-3 नीति सहायक होगी। हालांकि इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार के दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। जेनेटिक रूप से रूपांतरित (जीएम) फसलें जैव प्रौद्योगिकी की देन हैं, लेकिन ये तभी उपयोगी होंगी जब मिट्टी एवं खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी आशंकाएं पूरी तरह हल कर ली जाएं। जैव प्रबलिकृत (बायोफोर्टिफाइड) फसलें कुपोषण से जंग को आसान बनाती हैं, लेकिन जब हमारे पास श्रीअन्न की अनेक समृद्ध जलवायु अनुकूल फसलें उपलब्ध हैं तो उनकी खेती को बढ़ावा देना लागत सक्षम एवं पर्यावरण अनुकूल पहल होगी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दूध, चावल, आटा, नमक और तेल के फोर्टिफिकेशन को मंजूरी दी गई है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त बन गया है।

**दवाओं एवं टीके की उपलब्धता :** विश्व से हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए आविष्कार किए गए टीके से आज यह बीमारी काफी हद तक न सिर्फ नियंत्रण में है, बल्कि इसने कई जानें भी बचाई हैं। आज मधुमेह से लड़ाई में कारगर इन्सुलिन की उपलब्धता के पीछे जैव प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। कुछ वर्ष पहले आए कोविड महामारी के वैश्विक संकट में भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षमता का दुनिया ने लोहा माना। एक ओर जहां विश्व की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं असहाय नजर आ रही थीं, वहीं कोरोना वायरस जनित इस आपदा को परास्त करने में भारत ने जैव प्रौद्योगिकी को एक अहम हथियार बनाया। भारतीय विज्ञानियों ने जिस तरह जैव प्रौद्योगिकी की मदद से एमआरएनए वैक्सीन तैयार की, उससे कोरोना की जंग में भारत वैश्विक स्तर पर मानवता की पहल का केंद्र बना। विश्व के अलग-अलग देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत उपलब्ध कराए गए टीके जैव प्रौद्योगिकी का मानवता को एक बड़ा उपहार है। जैव अर्थव्यवस्था में जैविक दवाओं की सबसे अहम हिस्सेदारी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन द्वारा मंजूर की गई लगभग दो दर्जन दवाएं बाजार में 2025 तक उपलब्ध होंगी। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विगत कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। इसका लाभ भारतीय दवा उद्योग को हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 55 बायोफार्मा कंपनियों के आवेदन उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के तहत मंजूर किए जा चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी भारतीय रोजगार परिदृश्य में ठोस बदलाव लेकर आया है। आज देश में 2000 से अधिक बायो स्टार्टअप हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे स्टार्टअप्स की है, जो सिर्फ चार-पांच साल पुराने हैं। ऐसे में प्रारंभिक स्तर पर ही उन्हें यदि बाजार मुहैया कराए जाएं तो ये सफलता के नए मानक स्थापित कर सकते हैं।

**दिव्यांगता से लड़ाई में सहायक :** विज्ञान और तकनीक के इस मेल से उपजे बायो प्रिंटिंग जैसे नवाचार दिव्यांगता की लड़ाई को भी आसान बनाने में मददगार हैं। बायो प्रिंटिंग में वस्तुओं की प्रतिकृति तैयार करने के साथ-साथ उनमें संवेदन क्षमता भी विकसित की जाती है। 3डी और 4डी प्रिंटिंग में प्लास्टिक और धातु की जगह जीवित कोशिकाएं बायोइंक उपयोग में लाई जाती हैं। ये जैविक तत्व के संश्लेषण से प्राप्त होती हैं। बायो प्रिंटिंग जीन थेरेपी के साथ ही टिश्यू इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। इसमें टिश्यू या उसकी प्रतिकृति तैयार कर ली जाती है। इसमें व्यक्ति की दिव्यांगता के अनुसार कृत्रिम जैविक अंग तैयार किए जाते हैं। बायोनिक आंख, कांटैक्ट लेंस, स्पीच रिस्टोरर, स्मार्ट पिल, नर्व रिजनरेटर, पोर्टेबल डाइलिसिस, प्रोसिंथेटिक लिंब आदि तैयार करने में जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन होना चाहिए। हालांकि नई पादप प्रजातियों का विकास हो या मनुष्य एवं पशुधन की जैविक संरचना में बाह्य एवं आंतरिक बदलाव, इसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। नियमन के आभाव में इससे नई चुनौती भी पैदा होगी।

## जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़े शोध

देश में जैव प्रौद्योगिकी पर शोध एवं निवेश को हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा। पिछले केंद्रीय बजट में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय आवंटन में 16 प्रतिशत कटौती की गई थी। इसी तरह शोधकर्ताओं, अकादमिक जगत तथा उद्योग के बीच जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को व्यावहारिक रूप देने वाली जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बजटीय आवंटन में भी वृद्धि की आवश्यकता है। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो राज्यों के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं उनकी प्रयोगशालाओं में संसाधन का अभाव बड़ी चुनौती है। वहां शोध की पर्याप्त अवसंरचना न होने से जैव प्रौद्योगिकी विषयों के स्नातक तथा परास्नातक रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होते हैं। इस संकट से समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्योग जगत को भी आगे आना होगा।

हालांकि शोध एवं नवाचार के लिए सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भरता की मानसिकता भी ठीक नहीं। केंद्र सरकार ने बायो ई-3 नीति के साथ विज्ञान धारा योजना के लिए 10,579 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अगर जैव प्रौद्योगिकी आधारित शोध एवं विकास कार्यक्रमों को गति देने वाले विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा स्टार्टअप्स तक निवेश और नीतिगत प्रोत्साहन पहुंचता है तो यकीनन भारत को जैव अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता।

खरी-खरी

## सबसे ऊपर होंगे हिंदुस्तानी

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

एक और ओलिंपिक खत्म हो गया। हमारे दल ने जोर बहुत लगाया, पर वह पदकों के दहाई के दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। हमने पदक कम और दिल ज्यादा जीते।

वैसे कई बार लगता है कि यह ओलिंपिक पश्चिमी देशों का षड्यंत्र है। अपनी मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ते भारत के ईमानदार, सच्चे और मेहनती लोगों को नीचे दिखाने का गहरा षड्यंत्र। यह भी कोई बात है कि उन्होंने ऐसे-ऐसे खेल ओलिंपिक में रखे हैं, जिसमें पश्चिमी देशों को खुद महारत हासिल है। अरे! कोई ऐसा खेल रख कर देखो, जिसमें भारतीयों को मजा आता हो। कई बार लगता है कि यह ओलिंपिक बहुत बोरिंग भी है। वही पुराने सैकड़ों वर्षों के घिसे-पिटे खेल। पता नहीं कौन लोग हैं ओलिंपिक कमेटी में जिन्हें दुनिया के महान खेलों के बारे में जानकारी तक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत को आइपीएल की तरह अपना ओलिंपिक भी करवाना चाहिए। तब खिलाड़ी किसी भी देश का हो, जीतेगी अपने ही देश की टीम। फिर प्रतियोगिताएं भी वह रखी जाएं जिनमें भारत के लोगों को महारत हसिल हो। पान मसाला खाकर थूकने की प्रतियोगिता रखो। देखें। किस माई के लाल में दम है कि वह भारत के वीरों से जीत जाए। पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं कि हर ओलिंपिक में सोने का तमगा हमारा।

बहुत सी और भी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हम हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बस बात इतनी है कि लोगों ने इन्हें ओलिंपिक में शामिल नहीं किया है। ओलिंपिक में गप्पे मारने की प्रतियोगिता, दिन रात सोने की प्रतियोगिता रखवा कर देख लो। यही नहीं चाटुकारिता की प्रतियोगिता में हम भारतीयों का भला कौन मुकाबला कर सकता है? मुफ्त के खाने की प्रतियोगिता, हर बात पर दूसरे को कोसने की प्रतियोगिता, निठल्ले चिंतन की प्रतियोगिता में हमसे कौन जीत सकता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह मेरा सुझाव मानकर एक बार देखे। नई-नई प्रतियोगिताओं के साथ ओलिंपिक कराए। फिर देखना कि पदक तालिका में सबसे ऊपर होंगे हिंदुस्तानी।

## पोस्ट

समकालीन भारतीय राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी संभवतः ऐसे आखिरी नेता रहे, जिन्होंने पार्टी संगठन में सक्रिय रहकर नए नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को तराशने का काम किया।
उज्ज्वल शाह@UJJAVALSHAH2

आतिशी कितने वोट दिला पाएंगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना आसान लगता है कि वह जीतनराम मांझी या चम्पाई सोरेन नहीं बनेंगी।
सौरभ त्रिपाठी@Saurabh_LT

अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जीत से ईमानदारी साबित करने का एलान करके पूरी न्याय और दंड व्यवस्था की प्रासंगिकता को चुनौती दी है। यदि चुनाव जीतना ही ईमानदारी का प्रमाण है तो सब निर्वाचित नेता देवता है। शिव कांत@shivkant



हम जैसे भारतीय ईरान को अपना मित्र देश मानते आए हैं, लेकिन अब लगता है कि ईरान के शीर्ष नेता खामनेई जी उम्मा का नेता बनने के लिए भारत को अनब्रेड करना चाहते हैं। खामनेई जी शिया-सुन्नी ब्रदरहुड का नेता बनना चाहते हैं। वह शायद भूल रहे हैं कि ईरान के बाहर केवल भारत में ही शिया सुरक्षित महसूस करते हैं।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_



विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

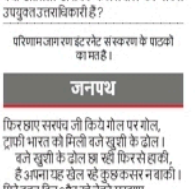

उत्तराखंड डायरी

# जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने बढ़ाई चिंता

पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। इधर मतांतरण, लव जिहाद एवं छेड़छाड़ के मामले सामने आने पर सरकार ने अब उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सीमांत पर स्थित है और इस स्थिति में यहां होने वाला जनसांख्यिकीय परिवर्तन सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य ही नहीं, अपितु देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को आवश्यक भी माना जा रहा है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत राज्य गठन के पहले ही हो गई थी। हां, इतना अवश्य है कि उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने पर इस प्रक्रिया में तेजी आई। आरंभिक लगभग 20 वर्षों तक राज्य सरकारें इसकी अनदेखी करती रहीं। अगर गहराई से आकलन किया जाए तो उत्तराखंड में नियोजित अथवा अनियोजित जनसांख्यिकीय परिवर्तन भविष्य के लिए खतरे की आहट कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से जिन जिलों की सीमाएं लगती हैं, उन मैदानी जिलों के शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों के लोग आकर बसे हैं। वैसे तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जमीन खरीद कर या अतिक्रमण कर बसने वालों में एक समुदाय विशेष की जनसंख्या काफी अधिक है। अब इनमें अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए घुसपैठिये एवं रोहिंग्या भी शामिल बताए जाते हैं।

समय बीतने के साथ ही राज्य के तमाम क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन अब साफ तौर पर दिखने भी लगा है। चाहे वह ऊधम सिंह नगर जिले की बात हो या हरिद्वार अथवा नैनीताल, देहरादून एवं पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों की। राजनीतिक प्रश्रय से पनपी अवैध बस्तियों में समुदाय विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है तो कई जगह घनी कालोनियों में उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। और तो और, अब पर्वतीय क्षेत्र के नगरों और पलायन के कारण खाली होते गांवों तक भी समुदाय विशेष की पहुंच चिंताजनक ढंग से बढ़ने लगी है। इससे सरकार के कान खड़े हुए हैं।

यह बात तक सामने आ रही है कि सुनियोजित लक्ष्य के तहत जंगलों और सरकारी भूमि पर धार्मिक अवसंरचनाओं के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए गत वर्ष प्रारंभ किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान यह बात सही साबित हुई। एक वर्ष के भीतर अकेले वन क्षेत्रों में 1360 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमणमुक्त किया गया। हैरत की बात यह कि धार्मिक अवसंरचनाओं के नाम पर किए गए इस अतिक्रमण में 500 से अधिक मजारें एवं चार मस्जिदें शामिल थीं। यद्यपि 50 छोटे मंदिर और दो गुरुद्वारे भी इस अभियान में हटाए गए। ऐसे में



उत्तराखंड का मानचित्र।

स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस दृष्टिकोण से धार्मिक अवसंरचनाओं के नाम पर सरकारी भूमि कब्जाई जा रही है।

ठीक है कि धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है, लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं, वह चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा रही हैं। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है और इसमें मजारों का कोई महत्व नहीं है। यह सही है कि साधु संतों की समाधियां यहां अवश्य रही हैं, लेकिन मजारों का इस भूमि से कोई नाता नहीं रहा है। जंगलों से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान न केवल मैदानी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में भी कई जगह वन भूमि पर कब्जा कर मजारें बना दी गई थीं, जिन्हें हटाया गया। यह स्वयं में सोचने वाला विषय है।

इस परिदृश्य के बीच राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून और सख्त भू कानून की मांग उठ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है। यद्यपि जनसंख्या नियंत्रण के विषय को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने संहिता की सीमा से बाहर रखा है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रेखांकित अवश्य किया है। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हिंदुओं की संख्या 83 प्रतिशत, मुस्लिमों की 13.9 प्रतिशत है, जबकि शेष जनसंख्या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की है। हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर जिलों में ही मुस्लिम आबादी क्रमश 34.3 प्रतिशत एवं 22.6 प्रतिशत बताई गई है।

अब सरकार ने भी राज्य में दिख रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए सत्यापन अभियान चल रहा है तो भूमि की खरीद के मामलों में पहले क्रेता एवं विक्रेता के सत्यापन और भूमि खरीद के उद्देश्य को स्पष्ट करना अनिवार्य किया गया है। यही नहीं, सरकार ने राज्य स्थापना दिवस से पहले सशक्त भू कानून लागू करने का इरादा भी जताया है। समान नागरिक संहिता कानून भी तब तक लागू होने की संभावना है। कुल मिलाकर, सरकार तो इन विषयों पर अपना काम कर रही है, लेकिन देवभूमि का स्वरूप बना रहे, इसके लिए सभी को सजग एवं सतर्क रहना होगा।

विशेषकर राजनीतिक दलों को इस विषय पर गंभीरता दिखानी होगी। केवल समुदाय विशेष को राजनीतिक हित में अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करने की रणनीति के बजाय राज्य के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने को प्राथमिकता देनी होगी।

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या ट्रंप पर एक और हमला उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा?**





सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

फिर छाए सरपंच जी किये गोल पर गोल,
ट्राफी भारत को मिली बजे खुशी के ढोल।
बजे खुशी के ढोल छा रही फिर से हाकी,
है अपना यह खेल रहे कुछ कसर न बाकी।
पिटे बहुत दिन और रहे चेहरे मुरझाए,
विश्व मंच पर आज पुनः हाकी में छाए!
- ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

# चुनाव में कांग्रेस शासित राज्यों की बात

हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा के गठन के लिए पांच अक्टूबर को चुनाव हैं। आठ अक्टूबर को मतगणना होगी और 12 अक्टूबर से पहले राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने के प्रयासों की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन आशीर्वाद रैलियों की श्रृंखला आरंभ कर चुके हैं। गत दिनों गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में मोदी की पहली रैली हुई, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति और कर्नाटक एवं तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा मतदाताओं से चुनाव पूर्व किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं होने का मुद्दा उठाकर हरियाणावासियों को सचेत किया। मोदी कांग्रेस के साथ-साथ आइएनडीआइए में उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की खराब वित्तीय स्थिति को भी पूरे देश के सामने रखने से नहीं चूके। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव से पहले किए गए वादों का न केवल बारीक पोस्टमार्टम किया, बल्कि केंद्र एवं राज्यों में होने वाली डबल इंजन की सरकारों के फायदे तक गिनाए। प्रधानमंत्री का कहना था कि किसान तो किसान होता है। भले ही वह हरियाणा का हो या कर्नाटक अथवा तेलंगाना का। कांग्रेस जब किसान हित की बात करती है तो उसे पहले कर्नाटक एवं तेलंगाना में किसान हित की योजनाओं को लागू कर दिखाना चाहिए।

प्रधानमंत्री राज्य के सोनीपत, पलवल और हिसार में तीन रैलियां और करने वाले हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां भाजपा सरकार सभी 24 फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद रही है। कांग्रेस लगातार केंद्र एवं भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर दबाव बना रही है कि एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती है तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों में किसान कल्याण की योजनाओं को धरातल पर क्यों लागू नहीं किया जाता? मोदी की इन दलीलों को खारिज करने के लिए कांग्रेस ने अपने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उतारा है, लेकिन चिदंबरम मोदी के आरोपों को नकारने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं।

हरियाणा के चुनावी रण में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ पंजाब की सरकारें हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निशाने पर। फाइल

दरअसल हरियाणा दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के साथ-साथ पंजाब की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी पिछलग्गू पार्टियों ने इन राज्यों को विकास के मामले में काफी पीछे धकेल दिया है। उनका भाव स्पष्ट था कि हरियाणा को यह गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती से बचने के लिए मोदी ने इन राज्यों के एक-एक कर उदाहरण दिए कि किस तरह से कांग्रेस द्वारा वहां चुनाव से पूर्व बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों की कमाई बढ़े और पैसे बचें, यही भाजपा की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वहां कर्मचारियों को अपना वेतन प्राप्त करने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्हें महंगाई भत्ता तक नहीं मिल रहा। हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के चलते मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को अपना वेतन छोड़ने का दिखावा तक करना पड़ रहा है। नई भर्तियां नहीं हो रहीं। कांग्रेस ने सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने का जो वादा चुनाव पूर्व किया था, उसे पूरा नहीं किया। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल और दूध सब महंगा कर दिया। हिमाचल की इस स्थिति को पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के झूठ ने कर्नाटक एवं तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा। कर्नाटक में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। विकास कार्य ठप हैं। कांग्रेस सरकार आने के बाद वहां नौकरी और निवेश, दोनों कम हो गए हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, यह कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। मोदी ने चुनौती दी कि अगर कांग्रेस में दम है तो वह कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी किसान संबंधी योजनाएं लागू करे।

हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा हरियाणा के लोगों के बीच सबका विकास-तेज विकास का नारा दे रही है। अब राज्य के लोगों को यह नारा कितना लुभा पाता है इसका पता तो आठ अक्टूबर को ही चलेगा जब मतपत्र की पेटियां खुलेंगी।

********

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 18 सितंबर 2024

# अधिक नहीं है समय

**जिन अप्रत्याशित** हालात में आतिशी को AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वही हालात उनके इस कार्यकाल को बेहद चुनौतीपूर्ण भी बना रहे हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है।

**चुनौतियों से घिरा काल |** पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया। उस अवधि में आतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया।

आतिशी : कामकाज पर रहेगी नजर

**संक्षिप्त कार्यकाल |** यह स्पष्ट है कि आतिशी को इस पद पर बहुत ज्यादा समय नही मिलने वाला। उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं – अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया- ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तब तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। ऐसे में अगर उन्हें अपने कामकाज की छाप छोड़नी है तो उसके लिए वक्त सचमुच बहुत कम है।

**समय पूर्व चुनाव की मांग |** दिलचस्प बात है कि उनकी पार्टी समय से पहले नवंबर में ही चुनाव करवाने की मांग कर रही है और BJP भी ललकारने की मुद्रा में इसके लिए खुद को तैयार बता रही है। वैसे सचाई यह है कि मतदाता सूची के नवीकरण जैसे तकनीकी मसलों की वजह से वक्त से पहले चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल है। वैसे AAP नेतृत्व भी वास्तव में अगर जल्द चुनाव चाह रहा होता तो सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देती। यानी चार-पांच महीने का वक्त आतिशी सरकार के पास है। देखना होगा कि वह इसका कैसा इस्तेमाल करती है।

**नए प्रयोग पर नजर |** देखने वाली बात यह भी होगी कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त अपने दो नेताओं की ऊर्जा का AAP किस तरह का इस्तेमाल करती है। दिल्ली में निश्चित रूप से उसकी लड़ाई BJP के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी, लेकिन हरियाणा जैसे राज्यों में उसके तेवर की परीक्षा इस लिहाज से भी होगी कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की एकजुटता को कितना पक्का माना जाए। कुल मिलाकर, दिल्ली में शुरू हुए AAP के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर सबकी नजरें होंगी।

## ऑफ़बीट

# एकाग्रता का संकट

सौरभ श्रीवास्तव

**पापा, पढ़ने** में मन नहीं लगता। क्यों? मन भागता है। याद करने बैठता हूं तो लगता है कि आर्ट कर लूं। आर्ट करता हूं तो लगता है कि फुटबॉल खेल लूं। खेलते वक्त मेसी, रोनाल्डो के विडियो याद आते हैं। उनमें खो जाता हूं और पास मिस कर देता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं पापा, पर हो रहा है।

यह मेरे और 12 साल के बेटे के बीच का संवाद है। इसे कई-कई बार दोहराइए और खतरे को महसूस कीजिए। 12 साल का बच्चा एकाग्रता के संकट से जूझ रहा है। क्या सिर्फ बच्चों के साथ ही ऐसा हो रहा या हम-आप भी इसके शिकार हैं? ज्यादातर बच्चे इस संकट से जूझ रहे हैं। कुछ कह पा रहे हैं, पर ज्यादातर खामोश हैं और लगातार दबाव झेल रहे हैं। समस्या की पड़ताल करने से पहले मैंने बेटे के साथ एक करार किया कि 15 दिनों तक खाली वक्त में न तो मैं मोबाइल फोन को हाथ लगाऊंगा न ही वह, टीवी भी नहीं देखेंगे। तो क्या करेंगे? किताबें पढ़ेंगे, आर्ट करेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो घर की सफाई करेंगे। मैंने बच्चे को तो शिक्षा दे दी पर खुद मोबाइल से दूर नहीं रह सका। उसकी नजर बचा कर फोन देख ही लेता था। यह योजना पूरी तरह तो कारगर नहीं रही पर दोनों का स्क्रीन टाइम कम हुआ। दोनों की एकाग्रता में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस बीच बच्चे का दूसरी समस्या से सामना हुआ। स्कूल से मोबाइल पर होमवर्क और असाइनमेंट आ रहे थे। उनका क्या किया जाए? बात 15 दिनों की थी तो मैंने उनके प्रिंट निकाले और बच्चे को दिए, पर ऐसा कब तक किया जा सकता है?

स्कूल वाले माता-पिता से कहते हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखें पर होमवर्क उसी पर भेजते हैं। समाधान बहुत सीधा-सा है। स्कूल डायरी, जो कि आज-कल खाली ही रहती है। पहले स्कूलों में डायरी पर होमवर्क और छुट्टी आदि की सूचनाएं लिखाई जाती थीं और टीचर उन्हें चेक करके साइन करते थे। लेकिन अब सब वट्सऐप ग्रुप पर है। छुट्टी की सूचना से लेकर होमवर्क तक। अब सोचिए बच्चा मोबाइल देखकर होमवर्क करेगा तो उसका चंचल मन रील्स या सोशल मीडिया या विडियो की ओर नहीं आकर्षित होगा? और यदि आकर्षित होगा तो इन्फॉर्मेशन के विस्फोट से उसकी एकाग्रता भी 'जख्मी' होगी। लेखिका अरुंधति रॉय अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं, आज से पहले शायद ही किसी जनरेशन ने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉसेस की होगी। बड़ा सवाल यह है कि सूचनाओं के इस विस्फोट से खुद को और बच्चों कैसे बचाया जाए? सिर्फ हमारे-आपके स्क्रीन का इस्तेमाल कम करने से बात नहीं बनेगी। पूरे इको-सिस्टम में बदलाव की जरूरत है वरना एकाग्रता जैसी चीज हमारी दुनिया से गायब हो जाएगी।

## एकदा

# निराला का विरोध

**साल 1907** की बात है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में महिषादल गांव के ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बालक 8 साल का हो चुका था। पिता पंडित रामसहाय त्रिपाठी को अपने बेटे का जनेऊ कराने की इच्छा हुई। वह फौज में थे और इसी के लिए छुट्टी लेकर गांव आए। गांव के पुरोहित ने उन्हें बताया कि उनका बेटा वहां भी खा लेता है, जहां का छुआ हुआ गांव के ब्राह्मण नहीं खाते। जनेऊ के बाद उस पर रोक लगानी होगी, नहीं तो पाप पड़ेगा। रामसहाय ने बेटे को सख्त हिदायत दी। 8 साल के उस बालक को वह हिदायत अजीब लगी। जनेऊ के पहले जहां खाना पाप नहीं था, जनेऊ के बाद वह पाप कैसे होगा? पिता से पूछने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन में विद्रोह ने घर बसा लिया। जनेऊ हुआ। तीन दिन तक सब ठीक चला, चौथे दिन बालक ने अपने मन की कर डाली। पुरोहित से अब रहा नहीं गया और अपनी बेइज्जती मानकर मिर्च-मसाले के साथ धर्म नष्ट होने की शिकायत उन्होंने रामसहाय से कर दी। 'सबसे बड़ा जाति अपमाना' वाली बात पिता को लग गई। उन्होंने बेटे को बहुत मारा। एक दिन बाहर से आकर बिना हाथ-पैर धोए वह रसोई में चला गया। रामसहाय का गुस्सा सातवें आसमान पर। उन्होंने बालक का एक हाथ और एक टांग पकड़कर तालाब में डूबो-डूबो कर सबक सिखाया, वह भी जाड़े की उस शाम को। पुरोहित को क्या हासिल हुआ, पता नहीं, लेकिन बालक में जड़ता और रूढ़िवादिता से लड़ने की क्षमता आ गई। आगे चलकर इस बालक ने प्रगतिशील विचारों का पोषण किया। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम का वह बालक आगे चलकर 'निराला' के नाम से मशहूर हुआ।

Subrata Dhar



संकलन : हरिप्रसाद राय

### तालिबान के क़ानूनों से मुश्किल होगा औरतों का जीना, इससे बेपरवाह कई देश बढ़ा रहे नज़दीकियां

# अफ़ग़ानों से कैसे किया दुनिया ने छल



हर्ष वी पंत

**दुनिया** लगातार संकट में ही दिख रही है। मध्य-पूर्व का युद्ध तो है ही, जो असल में कभी बंद ही नहीं हुआ, यूरोप भी युद्ध में बुरी तरह फंसा दिख रहा है, जहां मान लिया गया था कि वह इस तरह के संघर्षों से आगे निकल चुका है। इन तमाम उथल-पुथल के बीच दुनिया के एक खास हिस्से को करीब-करीब भुला दिया गया है, जो 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया था।

**तालिबान का नया कानून |** अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से अफगानिस्तान की ओर से दुनिया का ध्यान जैसे हट चुका है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह देश कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अफगानिस्तान बार-बार सुर्खियों में आ जाता है। पिछले महीने ही तालिबान ने सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा अनुमोदित नए कानून जारी किए। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से यह अफगानिस्तान में बुराई और अच्छाई वाले कानूनों की पहली औपचारिक घोषणा है।

**महिलाएं मुख्य निशाना |** ये कानून रोजमर्रा की जिंदगी के पहलुओं से जुड़े हैं, लेकिन इनका मुख्य निशाना हैं महिलाएं और लड़कियां, जो पहले ही छठी कक्षा से आगे की पढ़ाई करने और स्थानीय नौकरियां करने से रोकी जा चुकी हैं। महिलाओं को जब भी बाहर जाना हो, उनके साथ एक पुरुष अभिभावक होना जरूरी होता है। तालिबान ने व्यभिचार के आरोप में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े और पत्थर मारने का नियम फिर से लागू करने की भी घोषणा की है। महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र से बाहर रखने और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने के इस व्यवस्थित प्रयास को ठीक ही 'लैंगिक रंगभेद' कहा गया है।

**और सख्त पाबंदियां |** नए कानून अफगानिस्तान की 1.4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों की तकलीफ व पीड़ा को बढ़ाते हुए उनकी स्थिति को बदतर बनाने वाले हैं। अब महिलाओं के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने शरीर को हमेशा पूरी तरह ढके रहना अनिवार्य होगा क्योंकि 'प्रलोभन से बचने और दूसरों को बचाने के लिए' उनका चेहरा ढके रहना जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक जब भी कोई वयस्क महिला घर से बाहर निकलती है, तो उसे 'अपनी आवाज, चेहरा और शरीर' छिपाकर रखना होगा। यानी बुर्का डालकर भी कोई महिला सार्वजनिक रूप से कुछ गा, पढ़ या बोल नहीं पाएगी।

**पुरुष भी हैं जद में |** नए नियम समलैंगिकता, पशुओं की लड़ाई, सांस्कृतिक समारोहों को भी प्रतिबंधित करते हैं। किसी सार्वजनिक मौके पर या गैर-मुस्लिम छुट्टियों में संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लग चुका है। ये नियम पुरुषों पर भी लागू होते हैं, उनकी गतिविधियों को भी सीमित करते हैं लेकिन इनका खामियाजा खास तौर पर महिलाओं को भुगतना पड़ेगा।



AI Image

**क्या है खतरा**

- तालिबान ने घोषित किया नया कानून
- महिलाओं का जीना हुआ और मुश्किल
- आतंकी तत्वों को आज भी है संरक्षण

**संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं |** अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबायेवा के मुताबिक, 'यह अफगानिस्तान के भविष्य के लिहाज से परेशान करने वाला दृश्य है। मोरल पुलिसिंग करने वालों के पास असीमित ताकत आ गई है... वे किसी को भी धमकाने और हिरासत में लेने की स्थिति में आ गए हैं।' लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पहले ही अपने सबसे निचले स्तर पर है, ऐसे बयानों का कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

**बनने लगे हैं संपर्क |** साफ है कि तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद ज्यादातर देशों ने धीरे-धीरे तालिबान के साथ रिश्ते सामान्य बनाने शुरू कर दिए हैं। रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों से उनका ठीक-ठाक संपर्क स्थापित हो गया है। साल की शुरुआत में चीन ने पूर्व तालिबानी प्रवक्ता बिलाल करीमी को आधिकारिक तौर पर पेइचिंग में राजदूत मान लिया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक को अफगानिस्तान का राजदूत मान लिया।

**अमेरिकी रुख में नरमी |** यहां तक कि अमेरिका भी यह कहते हुए तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाने में लग गया है कि वहां के मानवीय संकट को देखते हुए आम अफगान आबादी की मदद करना जरूरी है। तमाम देशों में आम राय बनती जा रही है कि तालिबान को नजरअंदाज करते हुए अफगानिस्तान की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

**भारत की दुविधा |** भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए चुनौती ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अल कायदा समेत तमाम आतंकी संगठन आज भी अफगानिस्तान में गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। भारत हालांकि तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं है, लेकिन नई दिल्ली मानवीय मदद जारी रखने के लिए निचले स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। 2022 से भारत ने अपने काबुल दूतावास में एक 'टेक्निकल टीम' भी तैनात कर रखी है। जाहिर है, तालिबान 2.0 के साथ तालमेल बनाना दुनिया के लिए एक खतरनाक जुआ ही है, जिसकी कीमत वहां की महिलाओं को चुकानी पड़ रही है।

*(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)*

# कालिख गोल्डन ट्रायंगल की

बीते दिनों कंबोडिया से 600 भारतीयों की रिहाई हुई। ये लोग वहां जॉब स्कैम में फंसे थे। इनसे जबरदस्ती साइबर क्राइम कराया जा रहा था। एशिया के साउथ-ईस्ट हिस्से (गोल्डन ट्रायंगल) से यह कोई पहला केस नहीं है। क्या है यह ट्रायंगल और कितना बड़ा इसका जाल, आइए जानते हैं:

### गोल्डन ट्रायंगल

*गोल्डन ट्रायंगल एक कुख्यात क्षेत्र है, जो लाओस, म्यांमार, और थाईलैंड की सीमाओं के पास स्थित है। यहां कई SEZ हैं, जहां कानून की बहुत कम पकड़ है और अपराधी गिरोह स्वायत्तता के साथ काम करते हैं। यह क्षेत्र खासकर किंग्स रोमांस कसीनो के लिए बदनाम है, जहां ऑनलाइन स्कैम, मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध होते हैं।*

**लाओस:** गोल्डन ट्रायंगल, SEZ तस्करी और साइबर फ्रॉड हब।

### सामने आए नाम

सुदर्शन दरडे, CEO, लॉन्ग शेंग कंपनी, बोकेओ, लाओस

सनी गोंजाल्विस, निउ निउ और एल्विस डू (दोनों विदेशी)

### इन पर निशाना

आईटी और इंग्लिश स्पीकिंग भारतीय।



### ब्लैकलिस्ट

*म्यांमार भारतीय दूतावास ने 2024 में जारी की फ्रॉडियों की लिस्ट-*

- दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नै, वाइजैग, गोवा आदि में कुल 24 एजेंट्स।
- विदेशों में कुल 21 एजेंट्स, 7 दुबई से।
- 22 सस्पेक्टेड कंपनियां, अधिकतर म्यावड्डी या यांगून में।

(पूरी लिस्ट- shorturl.at/40KLL)

### धोखाधड़ी के तरीके

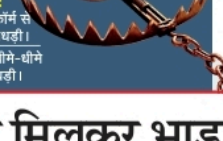

1. **रोमांस स्कैम:** सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स पर फंसाकर कराते हैं निवेश।
2. **क्रिप्टोकरंसी घोटाले:** फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लैटफॉर्म से हजारों डॉलर की धोखाधड़ी।
3. **पिग बुचरिंग स्कैम:** धीमे-धीमे भरोसा जीतकर धोखाधड़ी।



### घर वापसी

*यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग सबसे ज्यादा फंसे...*

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 150 भारतीयों की कंबोडिया और लाओस से। | 370 की म्यांमार, लाओस, कंबोडिया से। | 650 की कंबोडिया, और लाओस से वापसी। | 600+ भारतीयों को कंबोडिया से लाया गया। |



### काला कारोबार

**64B$** सालाना

**43.8B$** सिर्फ कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में।

कंटेंट: राहुल पाण्डेय

ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह



### तरीके

*फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, नकली वीजा एजेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस का झांसा, पैकेज डील्स, फर्जी इंटरव्यू कॉल्स, गलत सैलरी शीट, प्रोफाइल हैकिंग, फर्जी रिक्रूटमेंट एजेंसी, वेबसाइट पर नकली नौकरियों की लिस्टिंग।*

### दुनिया भर की दिक्कत

**कंबोडिया:** 2023 में, 1,00,000 से अधिक शिकार।

**म्यांमार:** 1,20,000 साइबर स्कैमिंग और मानव तस्करी में।

**लाओस:** गोल्डन ट्रायंगल SEZ में हजारों शामिल।

**शिकार**
तुर्की, ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, भारत, पाकिस्तान आदि।

### बचाव प्रयास



*विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास- कंबोडिया, म्यांमार, और लाओस से भारतीय नागरिकों को छुड़ाने में प्रमुख भूमिका।*

**ऑपरेशन इंटरपोल:** इस तरह की चीजों के खिलाफ इंटरपोल बड़े अभियान चला रहा है। भारत भी इसमें एक्टिव पार्टनर है

**प्रॉजेक्ट विक्टर (2023-2024)** साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जंग।

**प्रॉजेक्ट TORAID (2022-2023)** दक्षिण पूर्व एशिया में इंटरनैशनल वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई।

**ऑपरेशन फर्स्ट लाइट:** इंटरनैशनल एंटी-सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी अभियान।

(सोर्स : ProPublica, Interpol, OHCHR, CSIS, Asia Times, Pulitzer Center, UNODC, UN] Radio Free Asia, Diplomat)

# क्या कुछ चने मिलकर भाड़ फोड़ सकते हैं



कृष्ण प्रताप सिंह

**अवध की** एक पुरानी कहावत है, 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।' अकेले अपने दम पर कमाल कर दिखाने की डींग हांकते किसी 'मनबढ़' से कह दी जाए तो सिटपिटा कर रह जाता है। एक दिन एक मनबढ़ ने पलटकर पूछ ही लिया, 'बहुत से चने मिलकर तो फोड़ सकते हैं न?' तो कहने वाले को भी जवाब नहीं सूझा क्योंकि मौजूं जवाबी कहावत याद नहीं आई उसको- 'मढ़ो दमामो जात नहिं सौ चूहन को चाम'। यानी सौ चूहे मिलकर भी अपने चमड़े से नगाड़ा नहीं मढ़ा सकते।

यहां चूहों के बजाय चनों पर ही बने रहें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि चने के अकेले भाड़ न फोड़ सकने वाली कहावत उसकी बाबत कही जाने वाली इकलौती कहावत नहीं है। कहावतें कहने या बनाने वालों ने सोचा हो कभी शायद कि वह अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता तो उससे जुड़ी यह अकेली कहावत ही क्या कर लेगी। और यह सोचकर इकलौती न रहने दिया हो और उनकी झड़ी लगा दी हो। कहावतें कह-कहकर कोई किसी को चने के झाड़ पर चढ़ाए, नाकों चने चबवाए, खुद चने चबाकर बतियाए या एक चना दो दाल करे, उसकी मर्जी। चने का क्या, वह तो थोथा हो तो भी घना बज सकता है और चने खाकर बने रहने की गारंटी भी दे सकता है।

बहरहाल, अवध के लोगों को अपनी हर बात पर कुछ ज्यादा ही जोर देने की आदत है और कहावतें होती ही बात को जोरदार बनाने के लिए हैं। इसलिए जानें कब से दोनों चोली-दामन की तरह एक दूजे का साथ देते आ रहे हैं। क्या आश्चर्य कि वे दूला रानी तो उनके साथ हैं ही, जो हैं तो रानी, लेकिन इतनी बदकिस्मत कि 'जहां जायं दूला रानी, वहीं परै पाथर पानी', वह बूढ़ा 'सुग्गा' भी है, बढ़ती उम्र की मजबूरी के चलते जिसका राम-राम न पढ़ सकना भी कहावत बन गया है। हां, वह बेबस बुढ़िया भी उनके साथ है, जिसके जीवन की दुश्वारियां ऐसी हैं कि उसे 'सांस लेने' के लिए चरखा छोड़कर जांत (हाथ से चलाई जाने वाली घरेलू चक्की) चलाना पड़ता है।

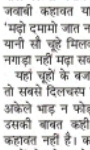

ऐसे में वह अभागी सुहागन ही उनका साथ छोड़कर कहां जाए, कंत के बिदेस चले जाने पर तो जिसकी किस्मत फूटी ही रहती है, वे घर पर रहें तो भी नहीं संवरती। कैसे संवरे, वे कभी रसबस उसके कुच तक नहीं गहते, जबकि वह उनके रिसिबस (गुस्से से भरकर) केश खींच लेने से भी आह्लादित होने को तैयार है। कहती है : कबहुं न रसबस कुच गहे, कबहुं न रिसिबस केस, का कंता के घर रहे औ का गये बिदेस।

AI Image



अवधनामा

लेकिन वह अकेली ही संतापित (पीड़ित) नहीं है और भी बहुत से लोग संतापित हैं, क्योंकि कहावतों में वह 'जबरा' भी है, जो अकेला होने के बावजूद भाड़ न फोड़ पाने वाला चना नहीं है। अपनी ताकत और क्षमता के गुरूर में कमजोरों पर गजब ढाता है, मारता भी है और रोने भी नहीं देता। वह सूप भी है, जिसमें कोई छेद नहीं, तो वह छलनी भी जिसमें बहत्तर (यहां गिनती पर मत जाइए) छेद हैं और यह कहकर मना करने के बावजूद कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, छलनी ही सबसे ज्यादा बोलती है।

क्यों न बोले, जब अपनी बारी पर जाड़ा भी बोल उठता है : लरिकन का हम छुअतै नही, जवान लगैं भाई, बूढ़ेन का हम छोड़तै नाही, चाहें ओढ़ैं सात रजाई। मजे की बात यह कि उसकी यह ढिठाई भी अनुत्तरित नही रहती। बोल उठता है कोई और : जाड़ा जाए रुई या जाड़ा जाए दुई। यानी जाड़े का गुमान भरपूर रुई से भरी निर्मित रजाई से पनाह मांगता है या दो आत्मीयों के परस्पर लिपटकर सोने से।

लेकिन इतना पढ़ते-पढ़ते आप सारी कहावतों को 'आत्मीय' ही मान बैठे हैं तो जान लीजिए, उनमें कई स्त्रियों, दलितों और वंचितों के प्रति बेहद अपमानजनक हैं। इसलिए कि जब वे पहली बार कही गईं, उस वक्त के वर्चस्ववादी समाज में इन वर्गों के अपमान को ही नहीं, उन पर अन्याय व अत्याचार को भी मान्यता प्राप्त थी। साफ कहें तो 'बहि-बहि मरै बैलवा, बइठे खायं तुरंग' वाली स्थिति थी। कहावतों के आईने में इसका अक्स भी नजर आना ही था।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

# किसने कह दिया संतोष का मतलब है रुक जाना

देवेन्द्रराज सुथार

**संतोष को** कई बार गलत समझ लिया जाता है। कुछ लोग इसे निष्क्रियता या आत्मसंतुष्टि के रूप में देखते हैं। लेकिन संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही रुक जाएं और आगे बढ़ने का प्रयास न करें। संतोष के जरिए हम अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखते हैं और उसका आनंद लेते हुए फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। संतोष शिथिल होने नहीं देता, बल्कि आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास जगाता है।

जहां संतोष की कमी हो वहां उपलब्धियों का आनंद नहीं मिल पाएगा। वहां कोई पड़ाव नहीं आएगा और लक्ष्य की ओर भागते-भागते हम हांफने लगेंगे, अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकेंगे। इसीलिए कहा गया है कि असंतोष हितकर नहीं है। जैसा कि शेख सादी ने कहा है, 'तृष्णा का प्याला पीकर आदमी विवेकहीन और पागल हो जाता है।' असंतोषी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, चाहे वह कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले। यह सोच उसे तनाव और अशांति में रखती है। संतोष और प्रगति परस्पर विरोधी नहीं, एक-दूसरे के पूरक हैं। महान विचारक इमर्सन ने इस संबंध को बखूबी समझाया है। उन्होंने कहा है, 'वर्तमान स्थिति को विकास के सोपान का एक पायदान मानें। विकास का सोपान अंतहीन होता है। इसलिए किसी पायदान को अंतिम मानकर वहीं न बैठ जाएं।'

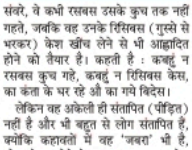

यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में संतोष का अर्थ है सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग। स्वामी विवेकानंद ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने अपने एक शिष्य को लिखे पत्र में बताया कि प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों के आश्रम अत्यंत समृद्ध हुआ करते थे। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ भौतिक विकास भी महत्वपूर्ण है। संतोष का अर्थ गरीबी या अभाव नहीं है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग और निरंतर विकास है। प्रकृति स्वयं हमें सिखाती है कि निरंतर विकास जीवन का नियम है। यदि ईश्वर ने अपनी सृष्टि में संतोष को स्थिरता के रूप में लागू किया होता, तो संसार हजारों-लाखों वर्ष पहले जैसा था, आज भी वैसा ही होता। लेकिन हम देखते हैं कि प्रकृति में निरंतर विकास और नवीनता होती रहती है। यह हमें सिखाता है कि संतोष का अर्थ स्थिरता नहीं, बल्कि विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

संतोष को जीवन यात्रा में एक पड़ाव के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में। लेकिन, फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि आगे और क्या हासिल किया जा सकता है। एक संतुष्ट व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी पिछली स्थिति से करता है। वह अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार आगे बढ़ने की योजना बनाता है। यह नजरिया व्यक्ति को अनावश्यक तनाव और ईर्ष्या से बचाता है। साथ ही उसे अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

संतोष इच्छाशक्ति का दमन नहीं है। जब हम संतुष्ट होते हैं, तो यह एक पड़ाव के समान लगता है। फिर नई सुबह में अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। संतोष हमें वर्तमान का आनंद लेना सिखाता है, जबकि महत्वाकांक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन दोनों गुणों के बीच सही संतुलन बनाकर हम एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 18 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com



## अनमोल वचन

*शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है*
-पंचतंत्र

## उत्साहजनक प्रयास

पूरी दुनिया को लगता है कि भारत इक्कीसवीं सदी के लिए सबसे अच्छी जगह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधी नगर में अपनी सरकार के पहले सौ दिन में देश की तेजी हो रही प्रगति पर बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आप हमारी प्राथमिकताओं, गति व पैमाने को आप देख सकते हैं। हमने तेज प्रगति के लिए हर क्षेत्र व कारक पर ध्यान देने की कोशिश की है। वे यहां वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक व प्रदर्शनी को संबोधित कर रहे थे। देश की विविधता, पैमाना, क्षमता, संभावना व प्रदर्शन को अद्वितीय बताते हुए वैश्विक अनुप्रयोग के लिए भारतीय समाधान बताया। मोदी ने कहा, हरित भविष्य



और शुद्ध शून्य उत्सर्जन केवल दिखावटी शब्द नहीं हैं। यह देश की जरूरत है और हम इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश के 2047 तक तक विकसित राष्ट्र बनने की बात को भी उन्होंने दोहराया। हालांकि यह कार्यक्रम वैश्विक मंच है। जहां अक्षय ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान, उद्योग व वित्तीय क्षेत्रों के दिग्गज एकसाथ आते हैं। सौर ऊर्जा स्थापना में गुजरात देश में अग्रणी हो चुका है। भारत की बड़ी आबादी में बिजली की बढ़ती खपत को लेकर सौर ऊर्जा के महत्त्व को सरकार द्वारा लगातार प्रमुखता से प्रोत्साहित कर रही है। स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में सरकार का लक्ष्य अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2015 में दिल्ली में की गयी थी। आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी व नार्वे इसमें हमारे प्रमुख साझेदार हैं। अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, यूएई व सिंगापुर को इसमें शामिल करने के लिहाज से विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि यह व्यापक फलक है इसलिए दुनिया भर से आए प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष अपनी सरकार के पहले सौ दिनों के कार्यों पर पीठ थपथपाने की आवश्यकता तो नहीं थी। मगर जैसा कि मोदी देश के आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात निरंतर अपने भाषणों में रखते हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, निजी क्षेत्र व उद्योगपतियों को इन नये क्षेत्रों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित तो किया ही है, जिससे आम लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। हरित भविष्य, सौर ऊर्जा तथा निम्नतर उत्सर्जन पूरी दुनिया के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस नाते इन सबका ख्याल रखना या इनके बारे में संवेदनशील बने रहना ज्यादा अहम है।

## खामेनेई के बिगड़े बोल

दुनिया में मुस्लिम देशों के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई में नही का नाम इस क्रम में शामिल किया जा सकता है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से वह दुनिया के विभिन्न देशों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। अभी उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर भारत के संबंध में बयान देते हुए कहा है कि यहां मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है। अयातुल्लाह खामेनेई की नजर में दुनिया भर के मुसलमान को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि 'अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर है तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए।' लोगों को याद होगा आज से



करीब 4 वर्ष पहले फ्रांस में मजहबी कट्टरपंथ के आधार पर हुई आतंकी वारदात ने पेरिस ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में धार्मिक विभाजन की चुनौती पेश कर दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने मुस्लिम संस्थाओं और जिहादी मानसिकता वाले धार्मिक नेताओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की घोषणा की थी। एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए थी तब खामेनेई ने मैक्रों की तीखी आलोचना की थी। हालांकि उनके इस तरह के भारत विरोधी बयान के बावजूद नई दिल्ली और तेहरान के बीच पारस्परिक संबंध सामान्य बने रहते हैं। पिछले 13 में 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर सहयोग के सामान्य ढांचे की समाप्ति के 8 साल बाद शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गौर करने वाली बात है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने चाबहार बंदरगाह पर समझौता करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया। खामेनेई 2019 में भी जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रम पर भारत की तीखी आलोचना की थी। इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने खामेनेई के झूठे बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को अन्य देशों के बारे में किसी तरह की टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। खामेनेई को इस तरह के बेसिरपैर वाले बयान देने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए इसका दोनों देशों के रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**प्रशंसनीय/ऋतुपर्ण दवे**

## काश, ऐसा देश भर में हो

कभी कभी बहुत मामूली सी बातें न केवल चर्चा का विषय बन जाती हैं बल्कि इतना कर जाती है कि पूछिए मत। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का है। जहां के कलेक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपनी दरियादिली और संवेदनशीलता से कइयों का दिल जीत लिया।

दरअसल, उनके दफ्तर में डरा-सहमा सा एक ग्रामीण मजदूर अपनी फिरयाद लेकर बहुत दूर से आया। दफ्तर में घुसते ही वहां का माहौल उसे असहज कर रहा था। इस बात का पता जैसे ही कलेक्टर को चला, उन्होंने उस ग्रामीण का सारा डर छूमंतर कर दिया। उन्होंने पूछा कि घर वापस पहुंचने में देर हो जाएगी तो रास्ते में खाने का क्या इंतजाम है? भोले मजदूर ने झोले से पोटली निकाल डरते-डरते बताया कि पत्नी ने कुछ पराठे बांध दिए थे। इतना सुनते हुए त्रिपाठी ने कहा कि मैं तुम्हारा काम तभी करूंगा जब तुम मुझे अपना पराठा खिलाओगे! यह सुनते ही मैले-कुचैले कपड़े पहना फरियादी असमंजस में पड़ गया और हिम्मत बटोर कर बोला मैं तो छोटा आदमी हूं, आप कहां मेरे पराठे खाएंगे? कलेक्टर त्रिपाठी ने तपाक से कहा कि छोटा-बड़ा कुछ नहीं, पराठा खिलाओगे तभी काम करूंगा। फिर क्या था, फरियादी ने झिझक से पोटली में बंधे हुए पराठों को कलेक्टर के सामने रख दिया। उसमें से एक टुकड़ा लेकर कलेक्टर ने खाना शुरू कर दिया। यह देख उनके मातहत भी अवाक रह गए। बाद में प्रशासन ने उनके लकवाग्रस्त भाई की सरकारी मदद की प्रक्रिया शुरू की। यकीनन ऐसे वाकये इक्का-दुक्का देखने को मिलते हैं। काश देश के हर जिले का अफसर चाहे वह छोटा हो या बड़ा; अगर इतनी संवेदना के साथ आमजन की समस्याओं को सुनने का मिजाज बना ले तो वाकई धरती स्वर्ग बन जाए। दरअसल, अधिकारी पॉवर में आने के बाद जनता से कटने लगते हैं। उनकी बातों का निपटारा करना तो दूर उनकी ठीक से फरियाद तक नहीं सुनी जाती है। यह तल्ख सचाई है। काश, यह घटनाक्रम एक नजीर के रूप में ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग में शामिल हो तो कितना अच्छा हो। बहरहाल अनजाने-अनचाहे ही सही, आईएएस त्रिपाठी के इस आचरण की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

# क्या वापसी कर पाएगी आप

दिल्ली



**डॉ. मनीष कु. चौधरी**

भारतीय राजनीति में जिस नैतिकता और शुचिता की दुहाई देकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी विवादस्पद छवि निर्मित की है; आज वह छवि बार-बार कलंकित और राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। यही कारण है की जो व्यक्ति जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देता है, वह व्यक्ति अपनी गिरती हुई छवि को बचाने और आगामी विधान सभा चुनाव में जन सहानुभूति के बल पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र का नाटक खेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक जीवन में जो कहा ठीक उसका उल्टा जीवन जिया है। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, तो उनकी पूंजी ईमानदारी और नैतिकता की थी, लेकिन धीरे-धीरे वह उन सारे राजनीतिक प्रपंचों और चालों में दक्ष होते चले गए जो एक गैर ईमानदार और भ्रष्ट नेता के लक्षण होते हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के कई राजनीतिक मायने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। उस स्थिति में केजरीवाल के पास त्यागपत्र देने के सिवा कोई अन्य सार्थक विकल्प नहीं है। केजरीवाल लगातार अपनी गिरती राजनीतिक छवि और भ्रष्टाचार से दागदार दामन को बचाने में असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र की घोषणा एक सोची-समझी राजनीति की पटकथा का हिस्सा है। हद तो तब हो गई जब 177 दिन जेल में रहकर सरकार चलाई गई। तब किसी को त्यागपत्र देने की सुध नहीं आई।

संवैधानिक संकट से जूझती दिल्ली की बदहाली अपने चरम पर है और इसकी चिंता किसी को नहीं है। आखिर 177 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अचानक मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने का ख्याल क्यों आया? केजरीवाल अपने इरादों और फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। यह फैसला भी अपवाद नहीं है। 13 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत के बाद यह कहना की जब तक दिल्ली की जनता चुनावी जनादेश के द्वारा उन्हें ईमानदार नहीं मान लेती तब तक दुबारा पद नहीं स्वीकार करेंगे। यह घोषणा अनेक प्रश्नों को जन्म देती है। इसका आम आदमी पार्टी, दिल्ली, विपक्ष और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल, केजरीवाल अपने त्यागपत्र के तीर से कई निशाना लगाना चाहते हैं। उनकी चाहत है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवम्बर में कराई जाए, जिससे उनके त्यागपत्र से उपजी सहानुभूति और ईमानदार होने के दावे को जनसमर्थन मिल सके। अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र अचानक फैसले का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। उन्हें




यह बात बखूबी पता है कि पिछले लोक सभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी दिल्ली की सातों लोक सभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया था। यह परिणाम भी आम आदमी पार्टी के कमजोर होने, अरविंद केजरीवाल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगने और शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा प्रमाण देने से प्रभावित हुआ है।

आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। विपक्ष की राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण इकाई आम आदमी पार्टी और चेहरा अरविंद केजरीवाल है। जिस कांग्रेस के विरोध और भ्रष्टाचार को कोसते थकते नहीं थे, उसी के साथ गठबंधन अवसर की राजनीति को दर्शाता है; जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते रहे हैं। कथित शराब घोटाले में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता का जेल जाना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मुद्दा देने का काम किया है। लोक लुभावन वादों को दिल्ली में एक हद तक आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों पर लोक कल्याणकारी सरकार का दवा करती है, लेकिन कार्यशैली में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। सिर्फ आंकड़ों के गणित से राजनीति नहीं चलती है। केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती दामन पर लगे भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के मुद्दे पर राजनीति में आने वाली पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार से चौतरफा घिरी दिख रही है। यह सबसे बड़ा संकट है। यह संकट सिर्फ त्यागपत्र देने भर से हल होने वाला नहीं है। अपनी जगह किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं वह भी रोचक होगा। यह पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में फिर से जीतने की रणनीति का हिस्सा है।

दिल्ली की जनता से ईमानदारी का प्रमाणपत्र मांगने का दांव चलकर विपक्ष की राजनीती और अपने धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पंहुचा पाते हैं; यह भविष्य के गर्भ में है। वैसे राजनीति सदैव संभावनाओं से पूर्ण होती है। अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका का पूर्ण लाभ लेंगे। समयाभाव की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए केजरीवाल स्वतंत्र होंगे। जेल जाने के बाद जिस तरह की सहानुभूति की उम्मीद थी उस उम्मीद पर दिल्ली की जनता ने पानी फेर दिया। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र के बहाने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया है। राजनीति का इतिहास यही बतलाता है कि त्यागपत्र के बाद राजनीतिक कद और मजबूत होती है। दिल्ली में केजरीवाल की लोकप्रियता घटी जरूर है, किंतु विपक्ष के जो भी संभावित चेहरे हैं, उनकी तुलना में आज भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी इस बदलती हुई परिस्थितियों, चुनौतियों और संभावनाओं के बीच से अपनी राह तय करेगा। केजरीवाल अपनी ठहरी हुई राजनीति में उफान लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए भी राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस को इससे थोड़ा फायदा मिल सकता है। विपक्ष ने लोक सभा चुनाव में जिस तरह बेहतर प्रदर्शन किया है, उससे पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं। केजरीवाल के मस्तिष्क में चंपई सोरेन की यादगारी जरूर ताजी होगी। आने वाला चुनावी मौसम बड़ा दिलचस्प होगा। वादों और इरादों, सच और झूठ, आरोपी और दोषी, विकास और पतन के बीच चुनावी मंजर क्या गुल खिलाएगी। उसका सभी को इंतजार रहेगा।

*(लेखक के निजी विचार हैं)*

भारतीय जनता पार्टी इस बदलती हुई परिस्थितियों, चुनौतियों और संभावनाओं के बीच से अपनी राह तय करेगा। केजरीवाल अपनी ठहरी हुई राजनीति में उफान लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए भी राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस को इससे थोड़ा फायदा मिल सकता है। विपक्ष ने लोक सभा चुनाव में जिस तरह बेहतर प्रदर्शन किया है, उससे पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं। केजरीवाल के मस्तिष्क में चंपई सोरेन की यादगारी जरूर ताजी होगी



**भारत में शोध एवं विकास पर निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी**

- शोध एवं विकास (आरएंडडी-रिसर्च एंड डवलपमेंट) पर निवेश आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, ताकि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और नतीजतन अर्थव्यवस्था बढ़ सके
- भारत बीते 20 वर्षों से जीडीपी का 0.7 फीसद ही आरएंडडी पर खर्च कर रहा है। इस्राइल के मामले में आंकड़ा 4.93 फीसद, द. कोरिया में 4.64, जापान में 3.26, जर्मनी में 3.09, चीन में 2.41 और अमेरिका में 3.47 फीसद है
- भारत को आरएंडडी निवेश को जीडीपी का एक फीसद बढ़ाना चाहिए ताकि देश में नवोन्मेषण के लिए माहौल बन सके

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)



अगर आज गणना हो जाए, तो अयोध्या में रामभक्तों से अधिक दूसरे राज्यों से आए हुए प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएंगे। आखिर क्यों अयोध्या की जनता इनके खिलाफ हिंसा पर उतारू है? क्या यह जांच का विषय नहीं है?

**रोहिणी सिंह, पत्रकार**
**@rohini_sgh**

## भरोसा बनाए रखना जरूरी



**जांच एजेंसी | प्रियंका सौरभ**

भारतीय न्यायपालिका को विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में स्वतंत्रता बनाए रखने का काम सौंपा गया है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल के फैसले जैसे कि अरविंद केजरीवाल आबकारी मामला और बिलकिस बानो मामला, इन तनावों को उजागर करते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं, बल्कि पत्रकारों, छात्रों और अकादमिक जगत से जुड़े उन लोगों को भी निशाना बनाती हैं, जो सरकार एवं उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिलसिला खासतौर से चुनाव के आसपास शुरू होता है।

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में चुनौतियां देखें तो राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों में, न्यायपालिका को अक्सर कार्यपालिका के सूक्ष्म या प्रकट दबाव का सामना करना पड़ता है। जब फैसले सरकारी हितों के खिलाफ जाते हैं तो यह विवादास्पद न्यायिक नियुक्तियों, तबादलों या राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकता है। जांच एजेंसियां अक्सर दोषसिद्धि सुनिश्चित किए बिना व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को हथियार बनाती हैं। पूछताछ के दौरान 'असहयोग' के लिए हिरासत को लंबे समय तक बढ़ाने की प्रथा को अक्सर कैद में रखने के बहाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, भले ही ठोस सबूतों की कमी हो। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार को कमजोर करती है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों द्वारा स्वचालित रूप से जमानत से इनकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भले ही कानूनी आधार इस तरह के इनकार को उचित ठहराते हों। न्यायमूर्ति भुइयां और न्यायमूर्ति बी.आर. दोनों गवई ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहते हैं, खासकर हाई-प्रोफाइल मामलों में। न्यायमूर्ति भुइयां की केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना लंबे समय तक हिरासत में रखने के आधार के रूप में 'स्पष्ट जवाब' या 'सहयोग की कमी' जैसे अस्पष्ट औचित्य को स्वीकार करने से इनकार को दर्शाती है। उनके फैसले में स्वतंत्रता से इनकार करने के लिए प्रक्रियात्मक देरी का इस्तेमाल करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की कार्रवाइयां संवैधानिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन करती हैं। यह न्यायमूर्ति



सूर्यकांत के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिन्होंने गहन जांच के बिना सीबीआई के तर्क को स्वीकार कर लिया। भुइयां की विस्तृत जांच व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बिलकिस बानो मामले में जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद दोषियों की रिहाई, इसी तरह न्यायिक परिणामों पर राजनीतिक प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। यह मामला इस बात का उदाहरण देता है कि सजा के बाद की राहत को माफी कानूनों के माध्यम से कैसे हेरफेर किया जा सकता है, अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की कीमत पर। संकट का एक कारण अदालतों से जुड़ा है। जिन मामलों में पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई हो या आरोपपत्र दाखिल हो गया हो, अक्सर उनमें भी जमानत नहीं दी जाती। कहीं-न-कहीं न्यायिक तंत्र स्थापित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा। समान अवसर का अभाव कानूनी प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है, जबकि यह स्थिति निष्पक्ष एवं निष्कलंक होनी चाहिए। यह भी जनता की नजरों से छिपा नहीं रहता कि कुछ खास न्यायिक अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती की जाती है, जिससे शक की सूई और गहरा जाती है।

कुल मिलाकर, न्यायिक तंत्र विशेषकर जमानत के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा। स्वतंत्रता के मूल्य को संविधान और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमन्य मान्यता के अनुरूप महत्त्व नहीं दिया जा रहा। जमानत के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी जिस हीलाहवाली का परिचय दे रहे हैं, वह गहन चिंता का विषय है। खासतौर से यह उन मामलों में मुख्यतः प्रकट होता है, जहां फंदा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर फंसा होता है। ऐसे मामलों में भले ही जांच पूरी हो जाए, लेकिन जमानत नहीं मिलती। यहां तक कि शीर्ष न्यायिक स्तर पर यह राहत नहीं दी जाती, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास करती है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले इसके कवच में दरारें उजागर करते हैं। केजरीवाल और बिलकिस बानो मामले न्यायिक अखंडता की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, खासकर जब कार्यकारी दबाव और प्रक्रियात्मक हेरफेर का सामना करना पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्यायपालिका को बाहरी दबावों का विरोध करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आरोपित परिस्थितियों के सामने। न्यायिक स्वतंत्रता और अखंडता के लिए इन खतरों के जवाब में, न्यायाधीशों को कार्यकारी हेरफेर और नियंत्रण से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रतिवादों को लागू करना अनिवार्य है।

*(लेखक के निजी विचार हैं)*

**क्रोध के दो मिनट | श्रीराम शर्मा आचार्य**



एक युवक ने विवाह के बाद दो साल बाद परदेस जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती को मां-बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहां ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया। यह तो मेरी कर्मभूमि है। इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा-मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग तो रहा था लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दीं। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया-कोई भी कार्य करने से पहले दो मिनट रुककर सोच लेना। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंच कर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। क्रोध में आकर वह तलवार निकालकर पत्नी पर वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 अशर्फियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया-कोई भी कार्य करने से पहले दो मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली-आपके बिना जीवन सूना सूना था। इस बीच पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा-बेटा जाग। तेरे पिता आए हैं। सेठ की पत्नी ने कहा- स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आंच न आए इसलिए इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन-पोषण और संस्कार दिए हैं।

## रीडर्स मेल

### जल का महत्त्व समझें

जल ही जीवन है। जल के बिना किसी भी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति प्रदत्त जल के दोहन से आज पूरी दुनिया के ऊपर जल संकट मंडराने लगा है। प्राकृतिक जलस्रोतों की अनदेखी की वजह से कई विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, कई स्थानों पर नदियों, पोखर आदि का अतिक्रमण हो चुका है। देश के 21 बड़े शहर जीरो ग्राउंडवाटर स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। देश में 80 फीसद बारिश मानसून सीजन में होती है। आज के विकास के दौर में भी हम सिर्फ 12 प्रतिशत बारिश के जल का उपयोग कर रहे हैं, शेष जल बर्बाद हो रहा है। यदि हम शेष जल को धरती के गर्भ तक पहुंचाने में सफल रहे, तो हमें सालों भर पानी की कमी महसूस नहीं होगी।

**हिमांशु शेखर, गया**

### दूसरों की खुशी हमारी खुशी

आश्रम में एक छात्र ने पूछा, गुरुवर क्या आसानी से खुशी पायी जा सकती है? गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह सभी विद्यार्थियों के समक्ष दूंगा। दूसरे दिन जब सभी छात्र विद्यालय आए तो गुरुजी ने कहा, आज हमलोग एक खेल खेलेंगे। बाईं तरफ स्थित कक्ष में कुछ पतंगें रखी हैं उन पर आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों को उस कक्ष में जाकर अपने-अपने नाम की पतंग लानी है और इस प्रांगण में आकर उड़ाना है। सभी छात्र कमरे में अपने नाम की पतंग तलाशने में जुट गए। अफरातफरी का माहौल बन गया, जिसके कारण किसी भी छात्र ने अपने नाम का पतंग नहीं खोज पाया। छीना-झपटी में पतंगें फट गईं। फिर से गुरुजी ने कहा, सभी अपनी नाकामी भूलकर दाईं तरफ स्थित कक्ष में जाएं वहां भी आप लोगों के नाम की पतंगे हैं, आपको किसी की भी पतंग लाकर उड़ानी है। सभी छात्र कुछ ही क्षणों में पतंग लेकर प्रांगण में आ गए और खुशी से पतंग उड़ाने लगे। तब गुरुजी ने उस शिष्य को कहा कि हम खुशी की तलाश इधर-उधर करते हैं जबकि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में होती है।

**संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड**

### प्रधानमंत्री ने तेज किया प्रचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए एक तरफ राहुल गांधी को 8.50 हजार रुपए की मासिक सौगात पर घेरा है वहीं कांग्रेस को दलित एवं ओबीसी आरक्षण विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने नई पेंशन योजना, 24 फसल पर एमएसपी एवं केंद्र सरकार की अपनी उपलब्धियां को जोरदार ढंग से रखा है। परिवारवाद पर भी देश के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अन्य दलों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार हरियाणा के चुनाव में पूरी ताकत से चुनौती दिखाई देती हुई कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा किया है। कश्मीर में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में सभी विपक्षी दलों को परिवारवाद, नफरत वाली और आतंकवाद पर चुप्पी साधने वाली पार्टी बताया। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस बार यहां विपक्षी दल भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे परिणाम जो भी हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है जिसका सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए.

**वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली**
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - स्नेहेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 183

# जारी रहे सुधार प्रक्रिया

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। संयोगवश मंगलवार को ही मोदी का 74वां जन्मदिन भी था जिसके बारे में सरकार की ओर से कहा गया कि उसे कई विभागों द्वारा 'सेवा पखवाड़ा' के आरंभ के रूप मे मनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। केंद्र सरकार ने पहले 100 दिन में कई निर्णय लिए हैं जिनमें कई अधोसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है। बड़े निर्णयों की बात करें तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए मंजूर कर दिया है। देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में, जो कि रोजगार तैयार करने के लिए आवश्यक है, सरकार ने 12 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। रोजगार का मसला हल करने के लिए नई सरकार के पहले पूर्ण बजट में कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई ताकि वे लोगों को काम पर रखें। इसके अलावा देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणा भी की गई।

सरकार ने पहले 100 दिन में कई निर्णय लिए हैं जिनका व्यापक संदेश यही है कि चरणबद्ध तरीके से सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह बात कैबिनेट निर्माण में भी नजर आई। अधिकांश आर्थिक और सुरक्षा संबंधी नेतृत्व पिछले कार्यकाल वाला ही है। बहरहाल, इस सरकार का ढांचा पिछली दो सरकारों से बहुत अलग है। 2014 के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने साझेदारों पर निर्भर है। अगर पहले 100 दिन को संकेत माना जाए तो उसे आगे चलकर साझेदारों के साथ और अधिक मशविरे और तालमेल के साथ काम करना होगा। यह लैटरल भर्ती के निर्णय को वापस लेने में भी नजर आया। गठबंधन के कई अहम साझेदारों ने इसमें आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए। इसके अलावा अब सरकार को अधिक मुखर और उत्साहित विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है जो 2014 के बाद अपनी सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

सरकारें और राजनीतिक प्रतिष्ठान जहां अक्सर घटनाओं से प्रभावित होते हैं और कई कारक बाहरी चुनौतियां भी सामने रखते हैं लेकिन पहले 100 दिन के प्रदर्शन को देखते हुए इस बात पर बहस हो सकती है कि आर्थिक निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी? जैसा कि बजट ने दर्शाया, सरकार वृद्धि और मध्यम अवधि की क्षमताओं को गति देने के लिए बड़े सार्वजनिक व्यय पर ध्यान केंद्रित रख सकती है। सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और एक संशोधित ढांचे की बात भी की है जिसे और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार राजकोषीय समेकन और उच्च पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन कैसे कायम करती है। व्यापक आर्थिक सुधारों की बात करें तो इसे बहुत अधिक कठिनाई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनौतियां चरणबद्ध हैं और समुचित मशविरे के बाद ही अंजाम दिए जाएंगे। सरकार पूंजीगत सब्सिडी और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन को भी जारी रख सकती है ताकि देश का औद्योगिक आधार मजबूत किया जा सके।

बहरहाल, देश को विनिर्माण क्षेत्र की अहम ताकत और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का महत्त्वपूर्ण भागीदार बनाने के लिए शायद केवल इतना ही पर्याप्त न हो। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार तैयार करने के लिए ऐसा आवश्यक है। इस संदर्भ में जैसा कि बजट में घोषित किया गया, सरकार सीमा शुल्क ढांचे की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे सहज बनाया जा सके और कारोबारी सुगमता में सुधार किया जा सके। हालांकि इस मोर्चे पर क्या हो रहा है इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि समीक्षा इतनी महत्त्वाकांक्षी होगी कि दरों में उल्लेखनीय कमी की जा सके और भारतीय उत्पादकों को वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सके। कुल मिलाकर इतिहास दिखाता है कि देश में गठबंधन सरकारें आर्थिक सुधारों को लागू करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि ऐसे उपाय सुविचारित ढंग से लागू किए जाएं। सरकार को 'एक देश, एक चुनाव' और समान नागरिक संहिता जैसे राजनीतिक विचारों को लागू करने में जरूर दिक्कत हो सकती है।

अजय मोहंती

# योग्यता बनाम जीन संरचना की बहस

**इस बात पर हमेशा बहस चलती है कि हमें सफलता किस चीज से मिलती है? हमारी जीन संरचना या हमारी अनुवांशिकी से अथवा हमारी शिक्षा दीक्षा और कड़ी मेहनत से? बता रहे हैं अजित बालकृष्णन**

मैं तीन सदस्यों वाली उस समिति का सदस्य था, जिसे भारतीय प्रबंध संस्थान के निदेशक का चयन करना था। इस पद के लिए पांच नाम छांटे गए थे। हममें से एक सदस्य ने कहा, 'इस अभ्यर्थी को चुन लेते हैं।'

मैंने पूछा, 'क्यों, उसके रेजूमे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं?' इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'मैं उसके पिता और भाई को जानता हूं...उनका परिवार प्रतिभाशाली और मेहनती है।'

मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, 'क्यों? क्या प्रतिभा खानदानी होती है?' उन्होंने जवाब दिया, 'हां, होती है। क्या आधुनिक विज्ञान साबित नहीं कर चुका है कि बुद्धिमानी तथा अन्य गुण जीन के जरिये एक से दूसरे में जाते हैं? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो 'द बेल कर्व' नाम की किताब पढ़िए।'

मैं अवाक् रह गया। मुझे पता था कि 50 वर्ष पहले भारत में (और शायद पूरी दुनिया में) सब कुछ 'पारिवारिक संपर्कों' की बदौलत हो जाता था और माना जाता था कि कौशल और प्रतिभा माता/पिता से बेटे/बेटियों में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या हम उस दौर को पीछे छोड़कर श्रेष्ठता को दूसरी बातों से नहीं मापने लगे थे? उदाहरण के लिए उसका रेजूमे या काम का पिछला अनुभव कितना सही है...

सच यह है कि जब हम सभी इंटरनेट तथा उससे जुड़ी नई ईजादों मसलन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आदि को समझने और सीखने में व्यस्त रहे तभी उतना ही चौंकाने वाली एक और तकनीकी लहर धीरे-धीरे हमारी जिंदगियों में उथलपुथल मचा रही थी, जिसका नाम था डीएनए।

डीएनए का पूरा नाम है 'डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड' और रसायनशास्त्री इसे अणु कहते हैं। पेचीदा रासायनिक नामों वाले और भी कई अणु हैं, जिनसे हम बेपरवाही दिखा सकते हैं मगर वैज्ञानिक डीएनए के बारे में जो दावे कर रहे हैं, वे डरावने हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, 'हर व्यक्ति में खास और अलग तरह का डीएनए होता है, जो माता-पिता से संतान में चला जाता है।'

अगर यह केवल रासायनिक पदार्थ होता, जो पशु, पक्षी और मनुष्य की हरेक प्रजाति में आलग-अलग होता तो भी हम इसे नजरअंदाज कर देते और वैज्ञानिकों को इससे माथापच्ची करने देते और सेमिनारों में इस पर बड़ी-बड़ी बातें करने देते। लेकिन अब तो और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।

इस क्षेत्र में इस कड़वी बहस की शुरुआत रिचर्ड जे हर्नस्टीन और चार्ल्स मरे की 1994 में आई किताब से हुई, जिसका शीर्षक हैः 'द बेल कर्वः इंटेलिजेंस ऐंड क्लास स्ट्रक्चर इन अमेरिकन लाइफ।' इस किताब ने जोर दिया कि आईक्यू परीक्षा में आंकी जाने वाली किसी व्यक्ति की बुद्धिमता का निर्धारण मोटे तौर पर उन जीन्स के जरिये होता है, जो उसे अपने माता-पिता से मिलते हैं। किताब ने चौंकाने वाली एक और बात कही। उसने जोर देकर कहा कि अलग-अलग नस्लों और जातीय समूहों में औसत आईक्यू भी अलग-अलग होता है क्योंकि यह उन्हें विरासत में मिले जीन से तय होता है। पुस्तक में विवाद खड़ा करने वाला एक दावा यह भी किया गया कि अमेरिकी समाज में आईक्यू द्वारा आंकी जाने वाली बुद्धिमता सामाजिक-आर्थिक नतीजों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। यह भी कहा गया कि अलग-अलग नस्लों में अलग-अलग आईक्यू होता है और समाज बोध की क्षमता से अधिक संतुष्ट होता जा रहा है और बोधपरक कुलीनता की ओर बढ़ता जा रहा है।

इस किताब ने बहुत अधिक विवाद पैदा किए मगर हममें से कई लोग इस बात पर चिंतित हैं कि डीएनए के बारे में चल रहा शोध गलत दिशा में जा सकता है और इसे सामाजिक आर्थिक भेद का आधार बताया जा सकता है। दूसरी ओर डीएनए से संबंधित शोध ही हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कुछ खास बीमारियां किन खास अनुवांशिक या रासायनिक कारणों से होती हैं। इस जानकारी की बदौलत ही हम नई दवाएं और इलाज तलाश पा रहे हैं, जिनसे कुछ खास बीमारियों का इलाज हो सकता है।

मेरे सांस रोककर बैठिए प्रिय पाठको! इन एकदम नई और क्रांतिकारी पहलों में से कई के केंद्र में एक तमिल व्यक्ति है, जिसका नाम है वेंकटरमण (वेंकी) रामकृष्णन। 1952 में तमिलनाडु के चिदंबरम में जन्मे वेंकी रामकृष्णन को 2009 में थॉमस स्टीज और अदा योनाथ के साथ रसायन विज्ञान के नोबेल से सम्मानित किया गया। मगर वेंकी को यह उपलब्धि भारत में शोध करते समय नहीं मिली। उन्होंने बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया और पीएचडी के लिए ओहायो विश्वविद्यालय चले गए। उसके बाद उन्होंने विभिन्न अमेरिकी शोध संस्थानों के जरिये काम किया। उनकी आत्मकथा 'जीन मशीन' बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है।

ये सब बहुत अच्छा लगता है मगर विचारक समुदाय में यह चिंता बढ़ती जा रही है कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस बात का है कि अच्छी शिक्षा के साथ प्रयास और कड़ी मेहनत से जीवन में सफलता मिलने की हमारी आधुनिक मान्यता की जगह यह धारणा न छा जाए कि विरासत में मिले जीन ही मायने रखते हैं। अति उत्साह में यह भी माना जा सकता है कि समाज के लिए जीन ही सब कुछ हैं और उनके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता।

यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे अतीत में देखा गया हैः तब हमने परमाणु की बनावट में महारत हासिल कर ली, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक केमिकल मिले और उसके बाद बाइट को मुट्ठी में करके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तैयार कर दिए। इसके बाद हमने मान लिया कि दुनिया को बेहतर जगह बनाने और समाज को फायदा देने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन हमने सीखा है कि जैसे परमाणु और बाइट को समाज के लिए नुकसानदेह बनने से रोकने के लिए उन पर नियंत्रण जरूरी है नवैसे ही शायद जीन को भी खास तौर पर 'जीन बनाम योग्यता' जैसी बहसों में नियंत्रण की बहुत जरूरत है।

*(लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं)*

# कार्य स्थलों पर दुष्चक्र में घिरी महिलाएं

**कोलकाता** के आर जी कर अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना और मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली रिपोर्ट का भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून इंडिया सूची के साथ पहली नजर में कोई संबंध नहीं दिखता। मगर सच यह है कि इनका आपस में लेना-देना है। पहली दो घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत में कार्य स्थलों पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुरक्षा का कितना अभाव है। फॉर्च्यून इंडिया की सूची बताती है कि अभी कुछ और समय तक स्थिति ऐसी ही क्यों रहने वाली है।

इसकी वजह कारोबार के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों (सीईओ) और प्रबंधन निदेशकों की सूची में नजर आती है। इस सूची में शामिल सबसे बड़ी 100 कंपनियों में से एक की भी कमान महिलाओं के हाथ में नहीं है। उनके बाद की कंपनियों की पड़ताल भी निराश करने वाली ही है। मगर फॉर्च्यून ने एसपीजेआईएमआर के साथ मिलकर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जो बताता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से बमुश्किल 1.6 फीसदी में प्रबंध निदेशक और सीईओ महिला हैं। शीर्ष 1000 कंपनियों की बात करें तो 3.2 फीसदी में नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है।

दूसरे देशों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। चीन का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से केवल 10.4 फीसदी को महिलाएं चला रही हैं। अमेरिका में भी अनुपात कुछ ऐसा ही है। मगर भारत इस पैमाने पर वाकई काफी पीछे है।

ऐसे सर्वेक्षणों की कमी नहीं है, जो बताते हैं कि महिलाओं द्वारा चलाई जा रही कंपनियां पुरुषों की कमान वाली कंपनियों से ज्यादा सफल हैं क्योंकि महिलाएं ज्यादा समावेशी कामकाजी माहौल बनाती हैं। हालांकि इन निष्कर्षों के पीछे दिए तर्क थोड़े संदेह भी पैदा करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी सर्वेक्षण यह नहीं बताता कि अगर ये कंपनियां पुरुषों के नियंत्रण में रहतीं तो क्या उनका प्रदर्शन खराब होता? मगर कार्य स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा में कमी और कंपनियों में महिला नेतृत्व के अभाव के बीच संबंध स्पष्ट और सीधा दिखता है।


जिंदगीनामा
कनिका दत्ता

इस तथ्य का पता सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों पर अशोक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकॉनमिक डेटा ऐंड एनालिसिस (सीईडीए) के एक अध्ययन से चलता है, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दर्ज कराए गए महिला यौन उत्पीड़न के मामलों का विश्लेषण किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2018 में एक आदेश में कहा था कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी सालाना रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस साल मई में प्रकाशित इस अध्ययन में सीईडीए ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध करीब 2000 कंपनियों में से 300 कंपनियों को शामिल किया। इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप श्रेणियों में से 100-100 कंपनियां ली गई थीं। आंकड़ों में अच्छी बात यह दिखी कि 2013-14 से भारतीय कंपनियों में यौन उत्पीड़न के दर्ज मामलों की संख्या बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि यौन उत्पीड़न की शिकार होने वाली पहले से अधिक महिलाएं इनकी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत कर रही हैं। किंतु सीईडीए की निदेशक अक्षी चावला कहती हैं कि शिकायतों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है मगर शिकायतों का समाधान कम हो रहा है।

हालांकि अध्ययन में इस बात का जिक्र नहीं है मगर ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से नहीं होने का एक कारण यह भी है कि कई कंपनियां शिकायत समिति ही नहीं बनातीं, जबकि 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम (पॉश ऐक्ट) के तहत ऐसी समिति का गठन अनिवार्य है। कुछ अरसा पहले उच्चतम न्यायालय भी इस पर 'असंतोष' व्यक्त कर चुका है। शीर्ष न्यायालय ने कुछ महिला पहलवानों की शिकायतों पर सुनवाई के बाद यह टिप्पणी की थी। पहलवानों ने कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में हुई जांच में पता चला कि देश के आधे से अधिक खेल महासंघों में ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक समितियां ही नहीं हैं। भारतीय कंपनी जगत में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं।

सीईडीए की रिपोर्ट में दो अहम बातें और भी हैं। पहली बात, मुट्ठी भर कंपनियां ही वास्तव में ऐसी शिकायतों की सूचना देती हैं और कई कंपनियों में वर्षों से ऐसी एक भी शिकायत का जिक्र नहीं आया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो प्रबंधन ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई है या वे महिलाओं को काम पर ही नहीं रखते, जिस कारण ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं।

संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर छोटे सर्वेक्षण भी हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि महिला कर्मियों को या तो पॉश ऐक्ट अथवा आंतरिक शिकायत समिति के पास जाने के अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता या वे उत्पीड़न होने, करियर खराब होने अथवा बदनामी होने के डर से शिकायत दर्ज नहीं करातीं। सीईडीए के अध्ययन में कहा गया है कि ज्यादातर मामले बड़ी कंपनियों से आते हैं क्योंकि वहां शिकायतें सुनने और हल करने की अधिक पुख्ता व्यवस्था होती है। मगर मझोली और छोटी कंपनियों में चिंताजनक हालात हैं क्योंकि मुट्ठी भर मझोली कंपनियां तो फिर भी जानकारी देती हैं किंतु छोटी कंपनियों से शायद ही ऐसा कोई मामला सामने आता है।

ये सभी लक्षण पुरुषों के वर्चस्व वाले कामकाजी माहौल के हैं, जहां प्रबंधन महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल तैयार करने की जरूरत को बिना डरे नजरंदाज कर देता है। मई में लिंक्डइन के एक अध्ययन में पता चला कि कंपनियों में नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 2001 से जस की तस बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार इसके लिए पूर्वग्रह, सामाजिक रीतियां संरचनात्मक बाधाएं जिम्मेदार हैं।

यह दुष्चक्र दिखाई तो आसानी से जाता है। महिलाएं अटपटे कामकाजी माहौल से दूर रहती हैं या उत्पीड़न होने पर काम छोड़ देती हैं, जिस कारण ऊपर बढ़ने और शीर्ष तक पहुंचने के लिए कम महिलाएं बचती हैं। शीर्ष पर महिलाओं की संख्या कम होने से ऐसा कामकाजी माहौल तैयार होने की संभावना भी कम हो जाती है, जो महिलाओं के लिए उचित हो। ऐसी हरेक बाधा स्त्री-पुरुष समानता को कमजोर करती है।

## आपका पक्ष

### पाकिस्तान में बलूच विद्रोह और भारत की सतर्कता

पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। हाल में संभवतः अपनी तरह के सबसे बड़े समन्वित हमले, अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा किए गए। इन घटनाओं ने फिर से बलूच विद्रोह को उजागर किया है, जो लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रेरित है। पाकिस्तान ने भारत पर अलगाववादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और ईरान पर उन्हें सुरक्षित ठिकाने देने का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को नकार दिया है। भारत को बलूचिस्तान में बढ़ती स्थिति पर पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखना होगी, खासकर जब जम्मू-कश्मीर में हो रहे विधान सभा चुनाव को बाधित करने का आतंकी प्रयास करेगा। जम्मू में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवाद या छद्म युद्ध करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। दूसरी ओर चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए विकसित किए जा रहे कुछ प्रस्तावित बुनियादी ढांचे, पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के विवादित क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। भारत ग्वादर बंदरगाह (बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में अरब सागर के तट पर स्थित) को लेकर भी चिंतित है, जो चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है। इसे न केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, बल्कि चीनी नौसेना के उपयोग के लिए दोहरे उद्देश्य वाले बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए भारत को पर्याप्त सतर्कता बरतनी होगी।

*सुधीर कुमार सोमानी, देवास*

जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पुलवामा में सुरक्षा में लगे जवान

### मुरादाबाद का पीतल- स्टील बर्तन उद्योग

मुरादाबाद का पीतल उद्योग विषयक लेख वहां के पीतल और स्टेनलेस स्टील के बर्तन उद्योग की वर्तमान स्थिति पर बहुत तर्कसंगत चर्चा करता है। आंकड़ों से इतर मुरादाबाद की विश्व ख्याति, बाजार, घरेलू उद्योग, राजस्व और शहर की समृद्धि में दशकों से पीतल और स्टेनलेस स्टील ही समाहित है। पीतल और स्टील की कीमत, लागत, लाभ, जनमानस की आवश्यकता और रुचि, आर्थिक स्थिति आदि सभी कारक व्यापार की प्रकृति, उत्पादों में परिवर्तन एवं विविधीकरण समय के साथ परिवर्तनशील है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद के समानांतर जगाधरी-हरियाणा, आगरा और दक्षिण भारत में बर्तन उद्योग और चीन से प्रतिस्पर्धा ने भी मुरादाबाद के बर्तन उद्योग को प्रभावित किया है। रोजगार सृजन के परिप्रेक्ष्य में एक बर्तन के बनने में ढलाई, छिलाई से अंतिम पैकिंग तक 15-20 लोगों का श्रम लगता है। वर्तमान में विदेशी बाजारों में मांग कम होने का कारण नोवल्टी के शोपीस में चीन के सामान का भी प्रभाव है और कई कंपनियां भी इस क्षेत्र में आई हैं। बर्तन उद्योग में भी नवोन्मेष और शोध की जरूरत है और विभिन्न धातुओं के मिश्रण से और बर्तन उद्योग के आधुनिकीकरण से बाजार फिर से गुलजार हो सकता है।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में मंगलवार को आठवें भारत जल सप्ताह सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुर्मू ने कार्यक्रम में जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल (बाएं) भी उपस्थित थे।

## चिंतन

# सौ दिनों में उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी-3 सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल से अलग इस बार पीएम मोदी के सामने कई तरह की चुनौनियां भी दिखाई दी। इसके बावजूद सरकार के कार्यकाल को कमतर नहीं आंका जा सकता। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो सवाल उठे कि पूर्ण बहुमत नहीं होने से पीएम मोदी का अंदाज अब वैसा नहीं रहेगा। यह बात बिल्कुल सही थी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और बहुत कुछ सहयोगियों पर निर्भर हो जाता है, लेकिन सरकार ने इन सौ दिनों में बेहतर प्रदर्शन किया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, रूस और यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि सरकार की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं को 14 स्तंभों में बांटा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं। बधावन में मेगा पोर्ट बनेगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट, अगत्ती मिनिकॉय में नई एयर स्ट्रिप बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और कई मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है। एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके, भत्ते और एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियों का ऐलान किया है। मिडिल क्लास को भी 100 दिनों में कई राहतें दी गई हैं। अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं। जिनमें 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। तीसरे कार्यकाल में मजबूत होते विपक्ष का दबाव कहीं न कहीं दिखाई भी पड़ रहा है। सरकार को कुछ मौकों पर कदम भी पीछे खींचने पड़े हैं। सरकार के पीछे हटने का पहला मामला अगस्त की शुरुआत में सामने आया, जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इसके तुरंत बाद प्रसारण सेवा विधेयक वापस कर लिया। सरकार ने नवंबर 2023 में डिजिटल और अन्य मीडिया के नियमन को कड़ा करने के उद्देश्य से एक मसौदा प्रकाशित किया था। उसके बाद अगस्त के ही महीने में सरकार ने सिविल सेवा के बाहर के लोगों से वरिष्ठ नौकरशाही पदों के लिए आवेदन मांगने वाले एक विज्ञापन को वापस ले लिया। इस विज्ञापन पर भी काफी हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि उसकी ओर से उठाए गए सवाल के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं, सरकार के सामने जाति जनगणना का मुद्दा है, जिसे विपक्ष लगातार उठा रहा है। सरकार ने जनगणना करवाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जाति जनगणना पर अभी रुख साफ नहीं किया है। वैसे इसकी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इन सौ दिनों में आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सबसे बड़ा मुद्दा तो खेती किसानी को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बेरोजगारी पर भी तत्काल नकेल कसना बहुत जरूरी है। आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

## चेतना

उमेश चतुर्वेदी



# सांस्कृतिक संकट से मुकाबले की कवायद में वनवासी समाज

भारतीय जनजातीय समाज विकास की आधुनिक अवधारणा के हिसाब से पिछड़ा है, आधुनिक शिक्षा से दूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह चेतन नहीं है और उसकी सोच पिछड़ी है। ज्ञान की आधुनिक अवधारणा के हिसाब से भले ही वह पिछड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह समाज ज्ञानवान नहीं है। प्रकृति, अपनी संस्कृति और अपने परिवेश को लेकर जितना वह समाज सचेत है, शायद ही नागर समाज भी उतना हो। जनजातीय समाज के इन गुणों, विशेषताओं और आधुनिक समाज से उसके तालमेल को बढ़ाने में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम 72 वर्षों से प्रयासरत है। आश्रम हर तीन वर्षों पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करा रहा है। इसी कड़ी के तहत इस बार हरियाणा के समालखा में तीन दिनों के लिए जनजातीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो 20 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस कुंभ में देशभर की सत्तर जनजातियों के करीब दो हजार प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जिसमें हर इलाके की जनजातीय संस्कृति की झलक होगी। जनजातीय समूह किस तरह अपने जीवनयापन के लिए जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय समाज किस तरह भारतीय और विशेषकर सनातन पद्धति और परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसे हर बार प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम का मानना है कि भारत आजकल सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

मौजूदा दौर में सांस्कृतिक स्तर पर आस्था पर लगातार संकट बढ़ रहा है। विशेषकर सनातनी आस्था पर चोट पहुंचाने और उसे दरकाने की कोशिश तेज हो गई है। आस्था की हानि संस्कृति की हानि है और संस्कृति की हानि पहचान की हानि है। इसका मतलब यह है कि आस्थाओं पर चोट पहुंचाकर विदेशी ताकतें भारतीय संस्कृति और पहचान पर चोट पहुंचा रही हैं। यही वजह है कि इस बार जनजातीय समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसी संकट को जताने-बताने और भारतीय समाज को इस संदर्भ में सचेत करने की कोशिश की जा रही है। बेशक पूरी दुनिया के हिंदू समाज में हर देवी-देवता के अपने विशेष पूजा-अर्चन विधान हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर समाज ने इन पूजा विधानों में अपनी परंपरा विकसित कर ली है। हर इलाके में पूजा के लिए स्थानीय जरूरतों और मजबूरियों की वजह से अपने-अपने परिधानों की भी व्यवस्था बना ली है। स्थानीय प्रभाव में पूजा की स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रसाद सामग्री के चयन का विधान भी है। कुछ इसी तरह देश के हर वनवासी समुदाय की अपनी-अपनी पूजा पद्धति है। एक तरह से ये पद्धतियां देश की बहुरंगी संस्कृति का प्रतीक हैं। समालखा के सम्मेलन के आखिरी दिन शाम को हर वनवासी समुदाय अपनी-अपनी पूजा पद्धतियों से अपने देवी-देवों की पूजा करेगा। करीब सत्तर समुदायों के लोगों की अपनी-अपनी पूजा पद्धतियों का एक साथ दर्शन वहां अलौकिक अनुभव का माध्यम बनेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जल, जंगल और जमीन से सीधे जुड़े सहज भावुक समाज की सज्जनता और पारंपरिक पूजा विधान एक तरह से अनूठे दृश्य रचने जा रहे हैं। सांस्कृतिक संकट से जूझने के लिए यह पूजा समारोह कितना महत्वपूर्ण है, इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस पूजा समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। जनजातीय पूजा की एक विशेषता यह है कि वह निजी नहीं, बल्कि सामूहिकता पर ज्यादा जोर देती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से बहत्तर साल पहले वनवासी कल्याण आश्रम को बाला साहब देशपांडे ने जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी ज्ञान परंपरा और संस्कृति से दुनिया को परिचित कराने के साथ ही वनवासी समुदाय के सामूहिक नेतृत्व को उन्हीं के बीच से उभारने के लिए शुरू किया था। इस यात्रा में वनवासी कल्याण आश्रम ने जो बड़ा काम किया है, वह है धर्मांतरण पर लगाम लगाना। ईसाई मिशनरियों का वनवासी समाज सहज निशाना रहा है। आश्रम मिशनरियों के इस नापाक उद्देश्य की राह में बड़ी बाधा बनकर उभरा है। आश्रम ने जनजातीय समाज से ही नेतृत्व को उभारने की बड़ी कोशिश की है। वनवासी समाज की सर्वांगीण उन्नति हो, वह सुसंगठित हो, राष्ट्रीय एकता के भाव पुष्ट हो, उनमें से ही सुयोग्य नेतृत्व विकसित हो, अपने विकास कार्यों की देखरेख करें और वनवासी समाज की अपनी समस्याओं का समाधान खोजे, इस उद्देश्य को लेकर वनवासी कल्याण आश्रम करीब पचास हजार गांवों करीब 13 सौ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के दम पर जुटा हुआ है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



कृषि

डॉ. अश्विनी महाजन

# जीएम पर नीति बनाना आसान नहीं

न्यायालय ने सरकार को जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह से, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से भी अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है, जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं, लोग न केवल चिंतित हैं, बल्कि जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं। जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं, ऐसे में कम संभावना है कि सरकार 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी।

हाल ही में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिक मोडिफाईड (जीएम) फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों और पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त विचार की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और पर्यावरण रिलीज के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति करोल ने फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सख्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में यह मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) वर्ष 2004 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार जीएमओ की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए।

इस मामले से एक नहीं, बल्कि कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत इतने लंबे समय से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इस मामले की जटिलताओं को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे। साथ ही पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। हालांकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह से, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से भी अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है, जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं, लोग न केवल चिंतित हैं, बल्कि जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं। जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं, यह बहुत कम संभावना है कि सरकार 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी।

यह पहली बार नहीं है कि जीएम फसलों के लिए परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है। इससे पहले, यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में, मंत्री जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं और



निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, वह जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है। सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और डीएमएच 11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जबकि डीएमएच 11 के डेवलपर (अनुसंधानकर्ता) के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है।

भारतीय सरसों और रेपसीड संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. धीरज सिंह के एक शोध पत्र के अनुसार, राजस्थान में किसानों द्वारा उगाई गई किस्मों आरएस 1706, आरएच 1424 और आरएच 725 की उत्पादकता क्रमशः 2613 किलोग्राम, 2604 किलोग्राम, 2642 किलोग्राम है। विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद, बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएं बेवजह नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत (लगभग 8000 करोड़ रुपये) चुकानी पड़ी, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था। वर्तमान डीएमएच 11 बीज को, हालांकि स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें भी बायर कंपनी की प्रौद्योगिकी के कुछ गुणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बौद्धिक संपदा का विषय किसान हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जीएम के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी (यदि डीएमएच11 को अनुमति दी जाती है), तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जीएम अपनाने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। आज, हम, हमारे गैर जीएम टैग के कारण, लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। एक बार जब खाद्य पदार्थों में जीएम की अनुमति दे दी जाती है, तो हम इस महत्वपूर्ण लाभ को खो देंगे, क्योंकि आयात करने वाले देश, जहां जीएम की अनुमति नहीं है, भारतीय खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है। इसका मतलब है, जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं। कई अन्य बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक समझपूर्ण नीति बनाने के अपने कर्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में बीज संप्रभुता पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षण और विकल्पों पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव शामिल हैं।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

## कथनी और करनी में न हो कोई अंतर



संकलित

दर्शन

सभी के हित का ध्यान रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वाह करना कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य का पालन यदि समुचित रूप से किया जाता है तो जीवन पूर्णतः गौरवान्वित बनता है। जो कर्त्तव्यनिष्ठ है। वह अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। वह परमार्थ पोषक एवं प्रामाणिक होता है। वह जैसा रहता है, वैसा ही करता भी है। ऐसी कथनी-करनी की एकरूपता से वह समाज में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है और प्रत्येक उससे प्रेरणाएं ग्रहण करता है। कर्त्तव्य परिपालन की बात करना और कर्त्तव्य परिपालन के नाम पर शोर-शराबा मचाना अलग बात है और कर्त्तव्यों के क्षेत्र में बिना किसी शोर-शराबे के समर्पित हो जाना अलग बात है। आज हम देखते हैं कि कर्त्तव्यों के परिपालन के लिए अक्सर लम्बे-चौड़े उपदेश दिये जाते हैं, पर जब कर्तव्य निर्वाह का अवसर आता है तो व्यक्ति दायें-बायें देखने लगता है। कटु सत्य तो यह है कि आज कर्त्तव्यों की चर्चा करने वाले लाखों हैं, पर कर्त्तव्यों के पावन पथ पर गतिशील होने वाले विरले ही हैं। कई बार मुझे चिंतन के क्षणों में लगता है कि आज व्यक्ति कर्त्तव्यों से विमुख हो गया है। इस विमुखता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता और अशांति का विस्तार हुआ है। कर्त्तव्यों के पावन क्षेत्र से भटककर कोई व्यक्ति कभी भी शांति का अहसास नहीं कर सकता। जीवन का गौरव और उसकी सार्थकता कर्त्तव्य पालन में ही है।

## कभी अपने बल पर घमंड न करें

संकलित

प्रेरणा

महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने-सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब-जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब-जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्रीकृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यदि ये न होता तो पता नहीं तुम्हारे रथ की क्या स्थिति होती। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का अहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यथा स्थिति का अच्छा से अवलोकन करे।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### ओजोन सुरक्षित तो हम सुरक्षित

ओजोन के संरक्षण के लिए ही 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजन दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के लगभग 45 देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पहली बार 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और इसके बाद से हर साल यह दिन मनाया जाता है। कुदरत का अनमोल तोहफा स्वर्ग जैसी धरती और धरती के संरक्षण के लिए कुदरत ने बहुत कुछ हमे दिया है। इसी तोहफे मे से एक है ओजोन परत। ओजोन परत का संरक्षण उसी तरह जरूरी है, जिस तरह हम बीमारियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं।

- चंदन साहू, दुर्ग

## करंट अफेयर

# भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर चिंतित हैं चीन, रूस



अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि चीन और रूस, भारत-अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ये संबंध समाज में विविध आवाजों को महत्व देने के साथ ही समावेशिता, शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हैं। प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित 'हडसन इंस्टीट्यूट' में भारत-अमेरिका संबंध पर टिप्पणियां करने के बाद एक सवाल पर कहा, 'आपको क्या लगता है कि चीन और रूस इस साझेदारी को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि हम दुनिया के बाकी हिस्सों में जीवन का ऐसा रूप पेश करते हैं, जो समावेशिता, शांति, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कानून के शासन के बारे में है और यह समाज में हर किसी की आवाज सुनने के बारे में है।' वर्मा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अमेरिका के कुछ विरोधियों के तौर-तरीकों से 'बहुत अलग हैं।' उन्होंने कहा कि इसी विशिष्टता के कारण राष्ट्रपति जो बाइडन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को 'इस सदी का निर्णायक संबंध' बताया है। 'क्वाड' पर एक सवाल के जवाब में वर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। अमेरिकी राजनयिक ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह समान विचारधारा वाले देशों के बारे में है।'

## ऑफ बीट

# दुनिया की आधी बड़ी झीलों में हो रहा पानी कम



दुनिया में 50 प्रतिशत से अधिक बड़ी झीलों में पानी की कमी हो रही है और इसकी प्रमुख वजहों में गर्म जलवायु और मानव उपभोग प्रमुख हैं। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के फांगफैंग याओ हैं। याओ ने कहा कि यह अध्ययन उपग्रहों और 'मॉडल' की एक श्रृंखला के आधार पर दुनिया भर की झीलों में जल भंडारण में परिवर्तन के रुझानों पर पहला व्यापक आकलन है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर के सूखने जैसे पर्यावरणीय संकट के सामने आने के बाद याओ और उनके सहयोगियों ने यह अध्ययन किया। उनके सहयोगियों में अमेरिका के कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय और कंसास विश्वविद्यालय के अलावा फ्रांस और सऊदी अरब के अध्ययनकर्ता भी शामिल थे। अध्ययन दल ने दुनिया की करीब 2000 सबसे बड़ी झीलों तथा जलाशयों के जलस्तर में हुए बदलाव पर गौर किया। पृथ्वी पर कुल झील जल भंडारण का 95 प्रतिशत हिस्सा इन 2000 जलाशयों में है। अध्ययन दल ने 1992 से 2020 के बीच उपग्रहों द्वारा ली गयी करीब ढाई लाख तस्वीरों का उपयोग किया और इस तरीके से दल ने सबसे बड़ी झीलों में से 1,972 जलाशयों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया।

## ट्रेंड

### पीएम आवास योजना



पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के साथ चाय पर उनकी जीवन यात्रा को सुना। इस योजना से महिलाओं को लाभान्वित होते देख विशेष प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि कैसे यह योजना और ऐसी अन्य योजनाएं जीवन बदल रही हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

### भारत का गौरव



एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी को 15 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर उनका और भारत का गौरव बढ़ाया है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

### इस्तीफा देना पैंतरेबाजी



अरविन्द केजरीवाल द्वारा सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित से दूर इनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी, किन्तु उनके जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो असुविधाएं व समस्याएं झेली हैं उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा?

-मायावती, बसपा सुप्रीमो

### सिनेमा 2024 का जश्न



दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने वाले जिन अभिनेताओं को दर्शक पसंद करते हैं, उन्हें बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचना होगा। 18,19 व 20 सितंबर को व्हिसलिंगवुड्स इंटरनेशनल में सिनेमा 2024 का जश्न मना रहा है।

-सुभाष घई, फिल्म निर्देशक

## अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

# केजरीवाल का इस्तीफा

## आप का भविष्य

**अरविंद केजरीवाल** द्वारा इस्तीफे की घोषणा से इस कदम तथा 'आप' के भविष्य के बारे में अनुमान लगाए जाने लगे हैं। बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस निर्णय के पीछे अनेक अनुमान लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच मतभेद हैं। कुछ इसे रणनीतिक कदम बताते हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि आंतरिक और बाहरी दबावों के कारण यह मजबूरी में उठाया कदम है। इस्तीफे से आम आदमी पार्टी-'आप' के भविष्य तथा इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनका वारिस कौन होगा। अपनी लोकरंजक राजनीतिक शैली के लिए विख्यात केजरीवाल ने अतीत में अनेक साहसी घोषणायें की हैं जो एक प्रकार से रणनीतिक जुआ थीं। अक्सर इनका उद्देश्य अपना मतदाता आधार मजबूत करना था। जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर उनका 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनका इस्तीफा एक और राजनीतिक जुआ होगा जिसका उद्देश्य केजरीवाल को सुर्खियों में बनाए रखना या 'आप' की हालिया चुनौतियों से ध्यान हटाना है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने हैं।

मजेदार बात है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और वे वहीं से सरकार चलाते रहे। उनका आरोप है कि भाजपा गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के फर्जी मामलों में फंसा कर जेल भेज देती है, उनको इस्तीफा देने को मजबूर करती है और उनकी पार्टी तोड़



देती है। वे इस बारे में बहुत मुखर हैं और उनका कहना है कि चाहे जो हो दूसरे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन इस पक्ष में भी मजबूत तर्क हैं कि उनका इस्तीफा केवल एक 'स्टंट' है जिसका उद्देश्य पार्टी को पुनर्जीवित करना है। उनका इस्तीफा संभवत: ईमानदार और निस्वार्थ नेता की उनकी छवि बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है जिससे आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। वे मतदाताओं के पास जाकर अपने इस्तीफे की कथा सुनाएंगे और स्वयं को 'पीड़ित' की तरह पेश करेंगे। चाहे केजरीवाल का इस्तीफा एक चाल हो या मजबूरी में दिया गया हो, पर निश्चित रूप से इसने 'आप' को महत्वपूर्ण मोड़ पर छोड़ा है। गठन के समय से ही केजरीवाल पार्टी का चेहरा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई के कारण पार्टी का प्रमुख मतदाता आधार अस्थिर हो सकता है। इसके अलावा उनके दूसरे प्रमुख साथी मनीष सिसोदिया को भी नया मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। 'आप' ने स्वयं को राष्ट्रीय दलों के विकल्प के रूप में पेश करने की दिशा में कठोर परिश्रम किया है। इसलिए उसने प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा तथा भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को प्रमुख मुद्दा बनाया। लेकिन पार्टी का भविष्य मुख्यत: केजरीवाल के नेतृत्व पर निर्भर रहा। उनका इस्तीफा पार्टी को व्यापक, ज्यादा स्थिर तथा परिपक्व संगठन के रूप में विकसित कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 'आप' के अनेक नेता उनका स्थान ले सकते हैं जिनमें संजय सिंह, आतिशी मरलेना, राघव चड्ढा या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हो सकती हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह केजरीवाल की पसंद पर निर्भर करेगा। ऐसे में 'आप' के भविष्य पर सवाल है कि क्या पार्टी अपने सर्वोच्च नेता के भ्रष्टाचार और कदाचार के अनेक मामलों में लिप्त होने के बावजूद अगले चुनाव में सत्ता में वापसी कर सकती है? इसका जवाब दिल्ली वासी बेहतर तरीके से दे सकते हैं।

# सामाजिक मुद्दों के टिकाऊ समाधान

**'सामाजिक बिजनेसों' में सामाजिक मुद्दों, जैसे गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण के टिकाऊ समाधानों को वित्तीय प्रगति से जोड़ने की क्षमता मौजूद है।**

**उत्तम चक्रवर्ती**
(लेखक, असोसिएट प्रोफेसर हैं)

दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास लक्ष्यों-एसडीजी के बारे में चर्चा लगातार तेज हो रही है। एसडीजी का संबंध भारत में समावेशी विकास से भी है। हालांकि, भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, पर समावेशी विकास की चुनौतियां भी बनी हुई हैं। तेज आर्थिक प्रगति के बावजूद संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा तथा अवसरों के बीच असमानतायें बनी हुई हैं जिससे जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हाशियाकृत है। इस संदर्भ में 'सामाजिक बिजनेस' की अवधारणा पर समाधान के रूप में लोगों का ध्यान जा रहा है जो एकसाथ सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का समाधान पेश कर सकते हैं। हाल ही में विकास की इस वैकल्पिक अवधारणा को देश में महत्व मिलने लगा है।

'सामाजिक बिजनेस' एक शक्तिशाली माडल है जिससे गरीबी, असमानता, स्वास्थ्यरक्षा एवं शिक्षा जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ ही यह वित्तीय रूप से टिकाऊ होते हैं। परंपरागत बिजनेसों में जहां शेयरधारकों का मुनाफा अधिकतम करने को प्राथमिकता मिलती है, वहीं सामाजिक बिजनेस सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए मिशन की तरह काम करते हैं। इससे पैदा होने वाले मुनाफे को पुन: इन्हीं बिजनेसों में लगा दिया जाता है ताकि इसका प्रभाव बढ़ सके। उद्यमिता का यह खोजी दृष्टिकोण खासकर भारत के लिए महत्वपूर्ण है जहां बाजार-संचालित समाधानों से सामाजिक खाई पाटने की संभावनायें असीम हैं। सामाजिक बिजनेसों का जन्म पिछले दशक में हुआ और भारत ने सामाजिक उद्यमिता में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। सामाजिक मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता, हमारी नौजवान जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तथा निवेश फंडों के बढ़ते प्रभाव के कारण अनेक क्षेत्रों में सामाजिक बिजनेस उभर कर सामने आ रहे हैं।

गरीब परिवारों को सस्ती सोलर लाइटें देने वाले 'सेल्को' जैसे संगठन तथा टिकाऊ कृषि व्यवहारों के माध्यम से आदिवासी किसानों को सशक्त करने वाले 'अराकू काफी' जैसे बिजनेस यह दिखाते हैं कि जन कल्याण के लिए बिजनेस कैसे किया जा सकता है। भारत की सामाजिक-आर्थिक विविधता भी सामाजिक खोजों के लिए उपजाऊ आधार प्रदान करती है। उद्यमी कृषि, स्वास्थ्यरखा, सफाई, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के खोजी तरीके निकाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत की विशाल सहकारी डेरी संस्था 'अमूल' जिन सिद्धान्तों पर काम करती है वे सामाजिक बिजनेस के निकट हैं। इससे वह किसानों को उचित वेतन सुनिश्चित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद भी उपलब्ध कराती है।

इसी प्रकार ग्रामीण भारत में काम करने वाला अलाभकारी संगठन 'गूंज' शहरी कचरे को लाभदायक उत्पादों में बदल कर गरीबी उन्मूलन व कचरा प्रबंधन में अपना योगदान दे रहा है।

1.4 बिलियन जनसंख्या वाले भारत को सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है। हालांकि, देश ने तकनीक व ढांचागत संरचना क्षेत्र में काफी प्रगति की है, पर करोड़ों लोग अभी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे स्वच्छ जल, स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षा और रोजगार अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परंपरागत सरकारी हस्तक्षेप तथा दान-आधारित माडल प्रभावी होने के बावजूद अक्सर टिकाऊ व व्यापक समाधान देने में विफल रहते हैं। सामाजिक बिजनेस माडल यहीं पर सामने आते हैं और वे बिजनेस तथा सामाजिक दायित्व के बीच खाई पाटते हैं। सामाजिक बिजनेस के क्षेत्रों में स्वास्थ्यरक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

हालांकि यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, पर यहां असमानता बड़े स्तर पर व्याप्त है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों की पहुंच अभी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक नहीं है। डा. देवी शेट्टी द्वारा स्थापित सोशल बिजनेस 'नारायणा हेल्थ' जैसे क्षेत्र इस मुद्दे का समाधान जनता को सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्यरक्षा प्रदान कर कर रहे हैं। भारत में शिक्षा क्षेत्र के सामने भी पहुंच, गुणवत्ता तथा सस्ता होने की समस्या खासकर ग्रामीण व हाशियाकृत समुदायों में बनी हुई है। 'टेक फार इंडिया' जैसे सामाजिक उद्यम इस कमी को पूरा करने के लिए गरीब स्कूलों से प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है जो 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को रोजगार देती है। लेकिन अक्सर छोटे किसानों को बाजारों तक पहुंच, कर्ज तथा टिकाऊ व्यवहारों के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 'देहान' जैसे सामाजिक बिजनेस संपूर्ण रूप से कृषि सेवायें दे रहे हैं जिनमें निवेशों का वितरण, फसलों की विविधता और बाजार संपर्क शामिल हैं। वे किसानों का सशक्तीकरण कर उनकी आय बढ़ा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता के रूप में भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे रहा है। इस क्षेत्र में सामाजिक बिजनेसों की व्यापक संभावनायें हैं। पर्यावरण-हितैषी व टिकाऊ उत्पादों का विकास सामाजिक बिजनेसों द्वारा किया जा रहा है। इससे शहरों में टिकाऊ फैशन तथा आर्गेनिक उत्पादों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक बिजनेसों को सक्षम बनाने में 'इंपैक्ट इन्वेस्टिंग' की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत वेंचर पूंजीपतियों के उलट 'इंपैक्ट इन्वेस्टर' केवल वित्तीय लाभ प्राप्त करने के बजाय मापन योग्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देते हैं। 'आविष्कार', 'एक्यूमेन' व 'ओमीड्यार' जैसे नेटवर्क प्रारम्भिक सामाजिक बिजनेसों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी देते हैं ताकि वे अपना विस्तार और प्रभाव बढ़ा सकें। भारत सरकार ने समावेशी विकास संचालित करने में सामाजिक बिजनेसों की क्षमता पहचानी है। 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे कार्यक्रम वित्तीय सहायता, संरक्षण तथा कर प्रोत्साहन दे कर अक्सर सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को सामाजिक समस्याओं से निपटने में सहायता मिलती है। लेकिन सामाजिक बिजनेसों के समक्ष अनेक समस्यायें भी हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक उद्यमों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए धन प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। परंपरागत वित्तीय संस्थान अक्सर सामाजिक उद्यमों को अत्यधिक जोखिम वाला मानते हैं क्योंकि वे मुनाफा बढ़ाने के बजाय सामाजिक प्रभावों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

सामाजिक बिजनेसों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय टिकाऊपन बनाए रखते हुए अपना प्रभाव बढ़ाना है। अक्सर सामाजिक उद्यम स्थानीय संपर्कों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं जिसके कारण वे भिन्न भौगोलिक स्थितियों में अपने प्रयोग आसानी से दुहरा नहीं पाते हैं। सामाजिक बिजनेसों के लिए नियामक ढांचा अभी विकसित हो रहा है। ऐसे में जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं को पार कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना तथा अनेक सरकारी एजेंसियों से व्यवहार करना बहुत अधिक समय की मांग करता है तथा इसमें बहुत खर्च होता है। सामाजिक बिजनेसों को अक्सर स्पष्ट विधिक पहचान न होने का सामना भी करना पड़ता है।

स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से 'सामाजिक बिजनेसों' को देश के सुदूर क्षेत्रों तथा वंचित जनसंख्या तक पहुंचने में आसानी हुई है। ग्रामीण उद्यमियों को छोटे कर्ज दिलाने से लेकर शिक्षा प्लेटफार्मों तक सामाजिक बिजनेस अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण सरकारी हस्तक्षेप जनधन-आधार-मोबाइल या 'जेम' है। इसने बैंक खातों को मोबाइल नंबरों और 'आधार' से जोड़ कर वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। इस डिजिटल ढांचे ने सामाजिक बिजनेसों को भी सशक्त बनाया है और वे डिजिटल भुगतान, बीमा तथा स्वास्थ्यरक्षा सुविधायें ज्यादा प्रभावशाली रूप से दे सकते हैं। सामाजिक रूप से सचेतन उद्यमियों की नई पीढ़ी विकसित हो रही है जिससे 'सामाजिक बिजनेसों' की संभावना आज पहले के किसी अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक हो गई है। कोविड-19 ने भी भारत में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।

# कर्म का चक्र और वैदिक ज्ञान

> श्राद्ध हिंदू/वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन पूर्वजों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन दिनों नक्षत्र ऐसे होते हैं कि दूसरे आयामों के द्वार खुल जाते हैं।

**अश्विनी गुरुजी**
(लेखक आध्यात्मिक शिक्षक हैं)



आत्मा एक भौतिक शरीर में अवतरित होती है जो विभिन्न क्रमपरिवर्तनों और संयोजनों में पाँच तत्वों से बना होता है, जो एक जीवनकाल में किए गए कर्मों के प्रकार के आधार पर जन्म-जन्मांतर में पुनर्जन्म लेता है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेती हैं, या तो इसलिए कि वे अपने लोक (पृथ्वी लोक) के कर्म चक्र से समाप्त हो चुकी हैं या इसलिए कि वे अस्तित्व के एक अलग आयाम में फंसी हुई हैं और मानव शरीर में प्रकट होने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका कर्म संतुलन उन्हें मानव जन्म के लिए पात्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आत्माएं या तो ऊर्जा के रूप में निलंबित रहती हैं और उन्हें भूत और आत्माएं कहा जाता है या वे अस्तित्व के एक अलग आयाम में चली जाती हैं जिसे पितृ लोक या पूर्वजों का लोक कहा जाता है। जब तक वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वे अस्तित्व के किसी भी आयाम या स्तर पर हों, उन्हें अपने कर्म संतुलन को संतुलित करने के लिए अपनी संतानों से ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वे फिर से पुनर्जन्म ले सकें। श्राद्ध हिंदू/वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन पूर्वजों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन दिनों नक्षत्र ऐसे होते हैं कि दूसरे आयामों के द्वार खुल जाते हैं और वे अपने प्रियजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ये पूर्वज अपने बच्चों और नाती-नातिनों पर निर्भर रहते हैं कि वे उनके नाम पर अच्छे कर्म करें और विशिष्ट मंत्रों का जाप करें, ये दोनों ही कार्य आत्माओं को इन अवांछित योनियों या अस्तित्व के स्तरों के बंधनों से मुक्त करते हैं।

परिवार के सदस्यों का मूल कर्तव्य है कि वे अपने प्रियजनों के नाम पर कुछ

संस्कार करें और दान-पुण्य करें तथा संरक्षक बनें। वर्तमान युग में देश के युवाओं को वैदिक विज्ञान की शक्ति और प्रभावकारिता तथा वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों के अभूतपूर्व ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से औपनिवेशिक आकाओं द्वारा हमारे लिए चुने गए तरीकों पर आधारित है, वे वेदों की शक्ति से भयभीत थे और इसलिए उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को नष्ट कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि हमें निरर्थक विज्ञान पढ़ाया जाए और अपने लाभ के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाए, जिसका उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति में विश्वास खो दें और औपनिवेशिक आकाओं का आँख मूंदकर अनुसरण करें। वे जो चाहते थे उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी के लिए जो अब तक सोच रहे होंगे कि यह लेख हिंदुत्व की बू आ रही है और यह काल्पनिक कथा पर आधारित है, मैं इतिहास के कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्राचीन दुनिया में, लगभग 4000 साल पहले मुख्य संस्कृतियाँ मिस्र, मेसोपोटामिया, रोमन, मायान आदि थीं और निश्चित रूप से हमारी अपनी संस्कृति थी।

हिंदू धर्म और वैदिक विचारों को छोड़कर, वर्तमान समय के किसी भी धर्म या विचारधारा का अस्तित्व नहीं था। सभी संस्कृतियों में प्रचलित दूसरी दुनिया और आत्मा की अन्य आयामों की यात्रा में विश्वास है।

पिरामिड उत्तर-दक्षिण दिशा में संरेखित हैं और उनमें शाफ्ट ओरियन बेल्ट के तीन मुख्य सितारों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सितारों और मानव उत्पत्ति का जन्मस्थान हो सकता है। पिरामिड बनाने के लिए इतने भारी पत्थरों को स्थानांतरित करने की तकनीक अभी भी मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, वैज्ञानिक आज भी इनसे हैरान हैं, वे तब और भी हैरान हो गए जब उन्होंने मोहनजोदड़ो में मानव अवशेषों की हड्डियों में रेडियोधर्मिता की उच्च मात्रा पाई, जो परमाणु विस्फोट का संकेत देती है। 4000 साल पहले जब ये सभ्यताएँ फल-फूल रही थीं, उस समय तीसरा युग या डायपर युग चल रहा था, अगर हम त्रेता युग में वापस जाने की कोशिश करें और रामायण युद्ध में इस्तेमाल किए गए विभिन्न हथियारों के बारे में पढ़ें, तो हमें एहसास होगा कि हमारे पूर्वज सृष्टि के काम करने के तरीके और लोकों और ऊर्जा की दुनिया के रहस्यों को जानते थे।

हिंदू संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो अन्य सभी संस्कृतियों से पहले की है और अभी भी सबसे बड़ा प्रचलित धर्म है, इसके मंत्र और अभ्यास बकवास नहीं हैं, बल्कि वे आज के मनुष्यों के लिए एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का उपहार हैं। यही कारण है कि यह आज तक जीवित है।

## आप की बात

### दिल्ली में हलचल

**दिल्ली** में राजनीतिक हलचल तेज है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेशक इस्तीफा देना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक राजनीतिक दांव हो और विपक्षी नेताओं द्वारा इस्तीफे के समय पर सवाल उठाने भी उचित हों, लेकिन दिल्ली वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि उनको एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री मिलने जा रहे है। दिल्ली वाले उम्मीद लगा सकते है कि दिल्ली में ऐसे रुके हुए काम तेज गति से होंगे तथा प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी जो अरविंद केजरीवाल तथा उनके मंत्रियों के जेल जाने से प्रभावित हो रही थी। हालांकि, नए मुख्यमंत्री को अपना कामकाज दिखाने के लिए 5 महीने की अवधि नाकाफी है। बारिश के दिनों में दिल्ली में भारी तबाही मची है, करंट लगने से और जल भराव से लोगों की जान गई है। उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री उप-राज्यपाल से अच्छे संबंध बना कर राष्ट्रीय राजधानी के सर्वांगीण विकास में जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल से भी उम्मीद करनी चाहिए कि वे दिल्ली में एलजी से लड़ाई करने के बजाय देश में विकास व आर्थिक प्रगति के बारे में आम आदमी पार्टी-आप का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें।

**–वीरेंद्र कुमार जाटव**, दिल्ली

### मोदी की तीसरी पारी

**दस वर्ष** का शानदार कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे हुए। बिल्लियों के भाग से छींका नहीं टूटा। सभी विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार के जल्दी ही गिर जाने का बार-बार भ्रम फैलाने के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने पूर्ण दृढ़ता के साथ ही 100 दिन में बता दिया के वे बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं और उनका हर एजेंडा पूरा होगा। बेशक अपने दम पर पूर्ण बहुमत में बीजेपी की 26 सीटों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ समझौते करने पड़े जो कि वर्तमान राजनीतिक हालातो में जरूरी थे। मगर वे सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आए और देश के लिए हितकारी श्रेष्ठतम निर्णय लेते रहे। विपक्षी दल अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मोदी अपनी दबंग शैली में ही काम करेंगे। आगामी दिनों में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव सरकार की मजबूत नींव का एक परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगी दलों, खासकर जदयू व टीडीपी को राष्ट्रीय विकास के साथ बिहार व आंध्र प्रदेश के विकास के बारे में भलीभांति समझा चुके हैं। भाजपा का दावा है कि उसके सहयोगी दल-एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर सहमत हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत निश्चित रूप से परिवर्तनकारी होगी।

**- सुभाष बुडावन वाला**, रतलाम

### शिमला में विवाद

**शिमला** में कुछ दिनों से मस्जिद गिराने की मांग का प्रदेश के सियासी दल तथा नागरिक समर्थन कर रहे हैं। यह मस्जिद शासकीय भूमि पर तथा चार मंजिल बनी है जबकि हिमाचल प्रदेश में ढाई मंजिल से अधिक निर्माण पर ही प्रतिबंध है। हालांकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी सरकार को शीघ्र निर्णय की मांग करनी चाहिए ताकि आंदोलनकारी शांत हो सकें। मंडी क्षेत्र में अवैध मस्जिद को लेकर जारी विरोध के मद्देनजर मस्जिद का कुछ हिस्सा मुस्लिमों ने ढहा दिया है, लेकिन यह केवल लीपापोती वाली कार्रवाई है। इसी कारण मंडी में भी अभी आंदोलन जारी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समय रहते ही कानून-व्यवस्था और शांति बनाने रखने का प्रयास करना होगा। प्रदेश की जनता का आरोप है कि पिछले सालों में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से अशांति बढ़ी है। इससे प्रदेश की जनसंख्या संरचना बदलने के प्रयास हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की घटनायें कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी की भी परीक्षा ले रही हैं कि वह बहुसंख्यक समाज को नाराज न होने दे क्योंकि इसका प्रभाव प्रदेश के साथ ही पूरे देश में कांग्रेस की संभावनाओं पर पड़ सकता है।

**- बी. एल. शर्मा**, उज्जैन

### कश्मीर चुनाव

**कश्मीर** विधानसभा चुनाव देश के अन्य राज्यों के चुनाव से कुछ अलग महत्व के हैं। यहां धारा 370 हटने के बाद एक नया वातावरण पैदा हुआ है जिसमें कश्मीरी जनता ने वर्षों बाद प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ समझा है। आतंकवादियों के जुल्म और वहां के बड़े नेताओं का पाक-परस्त रवैया कश्मीरी जनता अच्छे से समझने लगी है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी उत्पादों से लेकर जमीन जायदाद की कीमतों में भारी वृद्धि, पर्यटन में भारी वृद्धि, असुरक्षा की भावना समाप्त होने के साथ ही और कई प्रकार के सकारात्मक अनुभव कश्मीरी जनता को प्राप्त हुए हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में जनता को अपने जनप्रतिनिधि चुनने तथा इसके बाद उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए कामकाज का उन्हें नया अनुभव प्राप्त होगा। दशकों बाद कश्मीरी जनता बिना किसी भय के मतदान करेगी। चुनाव के दौरान पाकिस्तान और आतंकवादी कई तरह की परेशानियां खड़ी करने के प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि राज्य में प्रशासन, सुरक्षा बल तथा जनता इन षडयंत्रों को विफल करने और चुनाव में भारी मतदान करने में सफल होगी।

**- विभूति बुपक्या**, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।